Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

डाक पंजीयन संख्याः-एल-2/9/रजि0/ए0डी0/119/15-17

संस्करण : लखनऊ
वर्ष : 11
अंक : 137
पृष्ठ : 6
मूल्य : 1.00

हिन्दी दैनिक

मंत्र भारत

लखनऊ-मंगलवार,16 सितम्बर 2025

लखनऊ, प्रयागराज,ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम बोर्ड 4 नेपाल से सीखा सबक! भारत में आंदोलनों का अध्ययन 5 जल्द मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ

पीएम ने पूरा किया वादा

पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ

पूर्णिया (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को बिहार के पूर्णिया जिले में नवनिर्मित एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। यह टर्मिनल भवन न सिर्फ सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए हवाई सफर की नई सुविधाएं लेकर आएगा, बल्कि बिहार के क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को भी नई उड़ान देगा। पीएम मोदी की उपस्थिति में 76 सीटों वाला विमान अहमबाद के लिए और उसके बाद एक विमान कोलकाता के लिए भी रवाना हुआ। इसके साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया की जनता से नये एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का अपना वादा प्रधानमंत्री ने पूरा किया दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना श्उड़ानश के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन न केवल सीमांचल क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग को पूरा करेगा, बल्कि बिहार की हवाई कनेक्टिविटी को एक नई ऊँचाई भी देगा। इससे जहां स्थानीय लोगों की सुविधा बढ़ेगी, वहीं प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी। इस विमान सेवा का लाभ पूर्णिया प्रमंडल समेत आसपास के करीब एक दर्जन जिलों को मिलेगा। पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया अब बिहार का चौथा एयरपोर्ट है जहां से कामर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू हुई। इंडिगो एयरलाइन्स अहमदाबाद और पूर्णिया के बीच सप्ताह में तीन दिन उड़ानें भरेगा जिससे गुजरात जैसे प्रमुख औद्योगिक शहर से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। पूर्णिया पूर्वी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और इसके आसपास के शहरों सहरसा, मधेपुरा , सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, नवगछिया, फारबिसगंज के अलावा नेपाल और बंगाल के कई शहरों से इसका सम्पर्क है। पूर्णिया हवाई अड्डे के नवनिर्मित अंतरिम टर्मिनल भवन के शुरू होने से इस क्षेत्र में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। यह टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसकी नई इमारत बनाने के बाद यात्री प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अब विमानो कि आवाजाही शुरू होने और उनकी संख्या में वृद्धि के साथ यात्रियों को दिल्ली, पटना और अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी और नियमित हवाई सेवाएं मिलने लगेंगी। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल और सहरसा जैसे जिलों के लोग अब हवाई सेवाओं का लाभ अपने नजदीकी शहर से उठा सकेंगे।

देहरादून से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू, धामी ने किया विधिवत शुभारंभ

देहरादून (एजेंसी)। सीएम ने कहा कि देहरादून से एअर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं की शुरूआत हमारे राज्य में नागरिक उड्डयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का विधिवत रूप से फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के समग्र विकास और हवाई संपर्क विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सीएम ने कहा कि देहरादून से एअर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं की शुरूआत हमारे राज्य में नागरिक उड्डयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेंगलुरु से बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और निवेश के अवसरों को काफी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत के सबसे गतिशील शहरों में से एक के साथ छात्रों, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए संबंध भी मजबूत होंगे। हम एअर इंडिया एक्सप्रेस का स्वागत करते हैं और इस कनेक्टिविटी से हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद करते हैं।

कांग्रेस ने फिर निकाला भाजपा और अडानी कनेक्शन,लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार के भागलपुर में किसानों की जमीन ओने पौने दाम पर ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए पीएम मोदी के करीबी उद्योगपति गौतम अडानी को दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार की भागलपुर में गौतम अडानी की ऊर्जा संयंत्र के लिए 10 लाख आम, लीची सागवान के पेड़ काटकर किसानों की 1050 एकड़ जमीन एक रुपये की लीज पर उद्योगपति अडानी को 33 साल के लिए दी गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संयंत्र को लगाने का प्रस्ताव बजट में किया था लेकिन बाद में तय किया गया कि किसी निजी कंपनी को संयंत्र दिया जाए। अगस्त में इस संयंत्र के लिए बोली लगी और अब श्री मोदी के मित्र के लिए बिहार में किसानों को लूटा जा रहा है और उनकी जमीन को उनसे छीना जा रहा है।

पुलिस हिरासत में महिला चालक, हादसा में हुई वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल को यहां बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारने की आरोपी महिला को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई इस दुर्घटना में आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारी एवं हरिनगर निवासी नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वे दोनों गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे। महिला, जो कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी, और उसके पति भी दुर्घटना में घायल हो गए। गुरुग्राम के रहने वाले दंपति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूछताछ और कानूनी कार्यवाही के लिए हिरासत में ले लिया गया।

व्यक्ति ने दो नाबालिग बेटों के साथ ट्रेन के आगे लगाई छलांग, पिता की मौत, बच्चे गंभीर रूप से घायल

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने दो नाबालिग बेटों के साथ चलती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना दौसा जिले के बांदीकुई के बसवा में हुई। पुलिस के अनुसार, बबली (35) नामक व्यक्ति ने अपने दो बेटों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बसवा थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि शुरूआती जांच में यह सामने आया है कि पारिवारिक कलह के कारण बबली ने यह कदम उठाया। बबली जयपुर के भांकरोटा में मजदूरी का काम करता था और रविवार रात ही अपने पैतृक गांव नंदेरा लौटा था। उसके परिवार वालों ने बताया कि वह लंबे समय से पारिवारिक विवादों के चलते तनाव में था। हादसे के बाद, स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब दोनों बच्चों की हालत स्थिर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। इस घटना से गांव में शोक और सदमे का माहौल है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर लगाई अंतरिम रोक, कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का नहीं होगा अधिकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को इस मामले में अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि, कुछ धाराओं को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्वधारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। फैसला देते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान पर रोक रहेगी। इसके अलावा, कोर्ट ने फैसला दिया कि वक्फ करने के लिए 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी विचार किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए। फिलहाल वक्फ परिषदों में कुल 4 से अधिक गैर-मुस्लिम शामिल नहीं किए जाएंगे।

पंजाबः राहुल बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे, गुरुद्वारे में टेका मत्था और सभी के कल्याण की कामना की

अमृतसर (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं। अमृतसर में गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर कांग्रेस इकाई के नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। अमृतसर पहुंचने पर राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के पूरे नेतृत्व के साथ अमृतसर स्थित गुरुद्वारा श्री समाध बाबा बुड्ढा साहिब जी में मत्था टेका और सभी के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अन्य नेता भी उपस्थित थे। राहुल गांधी के स्वागत के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, राहुल गांधी हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं। उनका हमेशा एक ही संदेश रहा है कि श्सेवा करो और सेवा करते रहो। यह एक बहुत ही सकारात्मक सोच है, जो जमीनी स्तर पर लोगों में उम्मीद जगाती है। श राहुल गांधी के दौरे के बीच नवजोत सिंह सिद्धू की गैरमौजूदगी पर उन्होंने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी धनराशि आ रही है, उसे सिर्फ जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान, नवजोत कौर ने राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब के हित में काम करने की अपील की। पंजाब में बाढ़ को लेकर नवजोत कौर सिद्धू ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बाढ़ को लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारियां थीं? राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट के दफ्तरों का हाल दिखाएं। सरकार के पास हमेशा एक ही जवाब होता है, पैसे नहीं हैं। यह सोचते हैं कि लोग पैसे इकट्ठे करेंगे और दे देंगे। श इस मौके पर कांग्रेस नेता राज कुमार वेरका ने कहा कि राहुल गांधी का यह दौरा बेहद अहम है। वेरका ने बताया कि राहुल गांधी अजनाला और रमदास समेत गुरदासपुर क्षेत्र में जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। वे देखेंगे कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। कांग्रेस नेता वेरका ने यह भी बताया कि पार्टी अपने राहत कार्यों की समीक्षा करेगी, ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद समय पर पहुंच सके।

संजय राउत ने भारत-पाक मैच को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

पाकिस्तान के साथ खेलना ही अपराध और देशद्रोहः राउत

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलना ही एक अपराध और देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है, लेकिन उन 25 महिलाओं की मांग का क्या जो मिटा दी गई थीं? जब पाकिस्तान को घुसकर मारने का मौका था, तब भाजपा की सरकार पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान पर रविवार को जो हुआ क्या वह फिक्स मैच था। उस मैच पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए का सट्टा खेला गया, इसमें पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा मिला होगा। कल के मैच की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम एक हजार करोड़ रुपए मिले होंगे। संजय राउत ने कहा कि आप पाकिस्तान को हमारी महिलाओं की मांग मिटाने के लिए सक्षम बना रहे हैं। पाकिस्तान जीता या हारा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर मैच में डेढ़ लाख करोड़ का जुआ खेला गया। सब कुछ पहले से फिक्स करके ये मैच खेला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए यह मैच खेला गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सांसद संजय राउत ने सवाल किया कि क्या अमित शाह को ये सब नहीं पता है, क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता चला। भारतीय टीम की मैच खेलने की इच्छा नहीं थी, फिर भी सरकार ने उन्हें खेलने पर मजबूर किया।

सरकार का पांच साल में वाहन क्षेत्र को शीर्ष पर पहुंचाने का लक्ष्य : गडकरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार अगले पांच साल में भारत के वाहन उद्योग को दुनिया में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मूल्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि वाहन क्षेत्र सरकार को सबसे अधिक जीएसटी राजस्व देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य पांच साल के भीतर भारत के वाहन उद्योग को दुनिया में शीर्ष स्थान वाला बनाना है। गडकरी ने बताया कि देश में दुनिया की सभी बड़ी वाहन कंपनियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था। अब भारतीय वाहन उद्योग का आकार 22 लाख करोड़ रुपये है। इस समय अमेरिकी वाहन उद्योग का आकार 78 लाख करोड़ रुपये है। उसके बाद चीन (47 लाख करोड़ रुपये) और भारत (22 लाख करोड़ रुपये) का स्थान है। मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।

शीश महल सफेद हाथी जैसा, इस पर बर्बाद हुआ पैसा दिल्ली के खजाने में वापस लाया जाएगा: गुप्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि शीश महल बंगला एक सफेद हाथी की तरह है और दिल्ली सरकार को अभी इसके भाग्य के बारे में फैसला करना बाकी है। यह बंगला अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। गुप्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केजरीवाल द्वारा इस पर बर्बाद किया गया पैसा दिल्ली के खजाने में वापस आ जाए। साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब से लेकर पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में रहते थे, जिसे भाजपा ने शीश महल का नाम दिया था। पांचजन्य द्वारा आयोजित आधार इन्फ्रा कॉन्फ्लुएंस 2025 को संबोधित करते हुए गुप्ता ने आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर बंगले के निर्माण पर दिल्ली के लोगों की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने का आरोप लगाया। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने दौरान पुनर्निर्मित यह बंगला भ्रष्टाचार और महंगी आंतरिक साज-सज्जा तथा घरेलू सामान के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बन गया था। गुप्ता ने कहा, यह दिल्ली सरकार के पास सफेद हाथी की तरह पड़ा है और हम सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए।

बिहार: यूट्यूबर की पिटाई करने वाले मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं? तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से पूछे तीखे सवाल

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जाले विधायक और मंत्री जीवेश मिश्रा और उनके समर्थकों पर कथित रूप से एक यूट्यूबर की पिटाई और अभद्र व्यवहार करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पटना में सोमवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने सवाल पूछने पर एक पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें राज्य मंत्रिपरिषद से हटाकर जेल भेजा जाएगा। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ वोट के लिए यहां आ रहे हैं? क्या यह जंगलराज नहीं है? अगर यह जंगलराज नहीं है तो क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। वे खुद इस मामले को लेकर दरभंगा के जाले जा रहे हैं। मंत्री पद की एक गरिमा होती है। यूट्यूबर ने सिर्फ सड़क को लेकर एक सवाल पूछा था। इस मामले में कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जनता भी जवाब देगी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर निशाना साधा था। दूसरी तरफ, तेजस्वी यादव के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, श्तेजस्वी यादव को अपने पिता से कुछ सीख लेनी चाहिए, या यूं कहें कि उनके पिता को कुछ ज्ञान देना चाहिए था। उनके पिता ने चारा घोटाले से जो पैसा गंवाया था, उससे आज राज्य का बड़ा विकास हो सकता था।

मंत्र भारत

पूर्वांचल

लखनऊ-मंगलवार,16 सितम्बर 2025

कश्मीर से सेब का निर्बाध परिवहन और मिजोरम के लिए

पहला कार्गो परिचालन नए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलेगा

रेलवे की इन पहलों से न केवल स्थानीय किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

रेलवे की यह रणनीति सिर्फ माल ढुलाई का विस्तार नहीं है, बल्कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की ओर बढ़ता ठोस कदम है

गोरखपुर: भारतीय रेलवे ने सीमांत और दूर-दराज क्षेत्रों में अपनी माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के तहत एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत एक ओर जहां जम्मू-कश्मीर से सेबों की निर्बाध ढुलाई के लिए दिल्ली तक नियमित पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की गई है, वहीं मिजोरम में पहली बार सीमेंट से लदी मालगाड़ी भेजी गई है। रेलवे की इन पहलों से न केवल स्थानीय किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। कश्मीर घाटी के फल उत्पादकों को राहत देते हुए रेलवे ने 15 सितंबर से बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन के लिए एक विशेष पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है। यह सेवा प्रतिदिन संचालित होगी, जिससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सेब सही समय पर दिल्ली के थोक बाजारों में पहुंच सकें। पार्सल वैन की यह सेवा न केवल तेज और समयबद्ध है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गंतव्य के बीच में आने वाले स्टेशनों पर भी माल उतारने की सुविधा देती है। इससे किसानों और व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होने से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। इससे किसानों की आय में भी इजाफा होगा। मालगाड़ी की सुविधा से पहली बार जुड़ा मिजोरम: पूर्वोत्तर भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार मिजोरम के

सायरंग (आइजोल) स्टेशन के लिए मालगाड़ी सेवा शुरू की गई है। असम से 21 वैगन में सीमेंट लादकर रवाना की गई यह मालगाड़ी मिजोरम के निर्माण क्षेत्र को नई ताकत देगी। इससे न केवल निर्माण लागत घटेगी, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, सीमेंट, फ्ल, स्टील और अन्य सामानों के परिवहन के लिए मिजोरम तक मालवाहक ट्रेनें चलेंगी। इससे रसद लागत कम होगी और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा सीमांत भारत: रेलवे की इन पहलों को समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर और मिजोरम जैसे सुदूर भू-भागों को राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़कर रेलवे न केवल देश के एक कोने को दूसरे से जोड़ रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारत की आर्थिक प्रगति में भागीदार बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय बाजारों की क्षमता का सही उपयोग हो सकेगा और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। रेलवे की यह रणनीति सिर्फ माल ढुलाई का विस्तार नहीं है, बल्कि यह ह्यएक भारत श्रेष्ठ भारतह्न के विजन की ओर बढ़ता ठोस कदम है, जिसमें हर क्षेत्र, चाहे वो कितने ही दूरस्थ क्यों न हों, विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

भाजपा पर जमकर साधा निशाना, मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई थी

वाराणसी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने काशी के पिशाच मोचन कुंड पर पितरों का पिंडदान किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा सांसद अवधेश

प्रसाद ने गया जाने से पूर्व काशी में पितरों का पिंडदान पिशाच मोचन कुंड पर किया। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। डबल इंजन की सरकार व्यापार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। कहा कि चोरी की शुरूआत मिल्कीपुर से हुई थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने राम को लाया राम उन्हें लेकर आए हैं। हर मां का होना चाहिए सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के सवाल पर कहा कि किसी की भी मां मां होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की इस पर उन्होंने कहा कि देश का मान बढ़ाया है हालांकि मैच खेलने का पूरी जनता ने विरोध किया था लेकिन हमारी टीम ने जीत कर देश का मान बढ़ाया। हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे में अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे।

सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कर रहे अध्यक्षता

वाराणसी। पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर वाराणसी पहुंचे मंत्री हरदीप पुरी ने जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शुक्रवार को सर्किट हाउस में दिशा की बैठक शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

मंत्री हरदीप सिंह पुरी कर रहे हैं। पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर वाराणसी पहुंचे मंत्री हरदीप पुरी ने जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा शुरू कर दी है। इस दौरान सांसदों और विधायकों के साथ सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह और प्रिया सरोज भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा वाराणसी के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा कर रहे हैं।

बुजुर्ग महिला के गले से चेन खींचकर भागा उचक्का

बस्ती। शहर के महरीखावां मोहल्ले में शनिवार की रात हुई चेन स्नेचिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, मोहल्ले के निवासी आशीष सिंह अपनी पत्नी के साथ मार्केट हुए थे। घर पर उनकी बुजुर्ग मां अकेली थीं। रात करीब सात से आठ बजे के बीच वह वॉकर के सहारे घर के अगले हिस्से में बैठी हुई थीं।

उत्तर रेलवे

ई ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक/पी0एस0, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई ऑक्शन से सम्बंधित सूचना।

एडमिन यूनिट/जोन	लखनऊ–उ०रे०–मण्डल– वाणिज्य/उ०रे०
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-BOY-MX-167-25-1 (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	10.09.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	25.09.2025 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	25.09.2025 समय 11:30 बजे
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-BOY-MX-168-25-1 (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	10.09.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	25.09.2025 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	25.09.2025 समय 11:40 बजे
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-LLJ-MX-146-24-1 (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	10.09.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	25.09.2025 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	25.09.2025 समय 11:50 बजे
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-MBDP-MX-171-25-1 (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	12.09.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	29.09.2025 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	29.09.2025 समय 11:30 बजे
नीलामी सूची सं०/ लॉट सं०	PARKING-LKO-LKO-MX-156-25-3 (Parking Mixed)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	12.09.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	29.09.2025 समय 11:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	29.09.2025 समय 11:40 बजे
नीलामी का प्रकार	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है	E- Auction Module of www.ireps.gov.in

No: C/113-E-Auction Policy/2024/SKS Dt. 15.07.2025 2823/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि

गोरखपुर,: प्रमुख मुख्य इंजीनियर कार्यालय, गोरखपुर के सभागार में 15 सितम्बर, 2025 को भारत रत्न स्व० एम. विश्वेश्वरैया की जयन्ती पर ह्यइंजीनियर्स डेह्य का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि, मुख्य इंजीनियर/टी.एम.सी. श्री संजय यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि ने समारोह को सम्बोधित करते हुये इंजीनियरिंग कार्य को पूरी गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं दक्षता के साथ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे में संरक्षा सर्वोपरि है और इसी को ध्यान में रखते हुये सभी को दैनिक कार्यों में संरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। श्री नीलमणि ने पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रहे कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रेनों की गति बढ़ाने तथा यात्रा समय में कमी लाने हेतु रेलपथ सुदृढ़ीकरण के लिये कम्प्लीट ट्रैक, रेल एवं स्लीपर नवीनीकरण, प्लेन ट्रैक एवं टर्न आउट की डीप स्क्रीनिंग, टर्न आउट का नवीनीकरण, थिक वेब स्विच का प्रावधान तथा चैनल स्लीपर का एच-बीम स्लीपर से बदलाव आदि कार्य नियमित किये जाते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलपथ के बेहतर अनुरक्षण हेतु मशीनों के माध्यम से मेंटेनेंस पर फोकस किया जाता है, जिसके फलस्वरूप संरक्षा, सुरक्षा एवं राइडिंग कम्फर्ट में उल्लेखनीय सुधार होता है। इस रेलवे पर ट्रैक के सुदृढ़ीकरण हेतु डी.टी.ई., सी.एस.एम., ड्योमेटिक, यूनीमेट, एम.एफ.आई./एम.पी.टी., बी.सी.एम., डी.जी.एस./डी.टी.एस., टी28, पी.क्यू.आर.एस., यू.टी.वी., एम.डी.यू., एफ.आर.एम., बी.आर.एम. आदि प्रमुख मशीनें मेकैनाइज्ड तरीके से कार्य करती हैं। इन मशीनों का उपयोग प्लेन ट्रैक की टैम्पिंग एवं स्टेबलाइजिंग, टर्नआउट की टैम्पिंग, प्लेन ट्रैक एवं टर्नआउट की डीप स्क्रीनिंग तथा ट्रैक, रेल, स्लीपर एवं टर्नआउट के नवीनीकरण इत्यादि के लिये किया जाता है।

अखिलेश ने रिवॉल्वर तान फैक्टरी और संपत्ति पर कराया था कब्जा

कानपुर। किदवईनगर निवासी महिला उद्यमी ने पुलिस कमिश्नर से अधिवक्ता अखिलेश दुबे की शिकायत की है। किदवईनगर निवासी महिला उद्यमी नीति कपूर ने जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे के खिलाफ पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। आरोप लगाया कि अखिलेश ने फैक्टरी, मकान व अन्य संपत्तियों पर उसके भाई विपिन बजाज का कब्जा करा दिया था। विरोध करने पर रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस आयुक्त ने शिकायत एसआईटी को सौंप दी है। नीति ने बताया कि उनके लकवाग्रस्त पिता रमेश चंद्र ने सितंबर 2017 में तीन फैक्टरी व

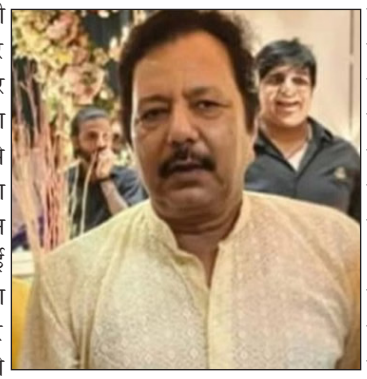

एक मकान उसके नाम वसीयत कर दिए थे। इसका पता चलने पर भाई विपिन माता-पिता को परेशान करने लगा। इस पर 2018 में पिता ने भाई विपिन और बहू के खिलाफ नौबस्ता थाने में शिकायत दर्ज कराकर उसके घर आकर रहने लगे। इस पर विपिन ने अपने साथी टोनू यादव के जरिये अखिलेश दुबे से मदद मांगी। नीति का आरोप है कि अखिलेश ने अपने रसूख के दम पर उनके पिता पर मारपीट व धोखाधड़ी के चार फर्जी मुकदमे करवा दिए और अपने गुर्गों की मदद से फैक्टरी और मकान पर कब्जा करवा दिया। मदद पाने की आस में पिता अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटते रहे। इसी तनाव में पहले मां स्नेहा और अप्रैल 2021 में पिता रमेश चंद्र का निधन हो गया। बताया कि 18 दिसंबर 2022 को टोनू यादव और उसके साथी अखिलेश के कार्यालय बुला ले गए। वहां अखिलेश ने कहा कि विपिन कारोबार में उनका साथी है। रिवाल्वर लगाकर कहा कि विपिन को परेशान करने या संपत्ति वापस पाने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अखिलेश ने भाई को आगे कर गोविंदनगर थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें जांच के बाद आरोप झूठे पाए गए थे। एसआईटी इस प्रार्थना पत्र के आरोपों की जांच कर रही है।

एक क्लिक पर अस्पताल में खाली बेड की मिलेगी जानकारी

वाराणसी। बीएचयू में इलाज कराने वाले मरीजों, तीमारदारों को अब परेशानी नहीं होगी। अब खाली बेड की जानकारी वेबसाइट और क्यूआर कोड के जरिये मिल जाएगी। आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में किस यूनिट में कितना बेड खाली है, कितने पर मरीज भर्ती हैं। अब इसकी जानकारी एक क्लिक पर घर बैठे मिल जाएगी। इस तरह की सभी जानकारी ट्रॉमा सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा परिसर में जगह-जगह क्यूआर कोड भी लगवाया गया है, जिसको स्कैन कर पूरी जानकारी ली जा सकेगी। इससे मरीजों, तीमारदारों को बेड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा विभागवार डॉक्टरों के नाम, उनकी उपलब्धता, मिलने वाली सुविधाओं के लिए भी भागदौड़ नहीं करनी होगी। ट्रॉमा सेंटर में वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश आदि जगहों से सड़क एक्सीडेंट सहित अन्य घटनाओं में घायल मरीज आते हैं। यहां कुल 354 बेड पर इलाज की सुविधा है। आम तौर पर इमरजेंसी से लेकर आईसीयू और वार्ड में बेड खाली होने की सही जानकारी न मिलने पर दूर दराज से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भटकना पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि अब वेबसाइट पर एक ही जगह डॉक्टरों के नाम, विभाग से जुड़ी जानकारी के साथ ही बेडों की उपलब्धता के साथ ही मरीजों, तीमारदारों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी

भी 22 बिंदुओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। वेबसाइट पर इमरजेंसी सहित कई नंबर दिए गए हैं, इसके माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। इसमें ओपीडी के शेडयूल की भी जानकारी भी रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

स्वच्छता कार्य के उपरान्त स्वच्छ दिखता गोरखपुर स्टेशन सरकुलेटिंग एरिया

गोरखपुर, : भारतीय रेल पर मनाये जा रहे स्वच्छता अभियान के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 15 सितम्बर, 2025 को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ एवं वाराणसी मंडलों पर स्वच्छता सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह अभियान रेलवे के सभी क्षेत्रों जैसे- स्टेशनों, ट्रेनों, स्टेशन परिसरों, कॉलोनियों, कार्यालयों, डिपो एवं कारखानों आदि में स्वच्छता के प्रति हमारे प्रयासों को सार्थक करेगा, साथ ही रेल कर्मियों एवं यात्रियों के बीच जागरूकता को भी बढ़ावा देगा। 15 सितम्बर, 2025 को लखनऊ मंडल पर मंडल रेल प्रबन्धक/लखनऊ श्री गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में सभी प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कोचिंग डिपो में बायो-ट्वायलेट चैम्बर की सफाई की गई, स्टेशनों पर लगाये गये डस्टबिन की धुलाई की गई, रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों को साफ किया गया तथा सभी स्टेशनों, स्टेशन परिसरों एवं टेज्नों में स्वच्छता कार्य किया गया और यात्रियों को स्वच्छता बनाये रखने के लिये जागरूक किया गया। इज्जतनगर मण्डल पर मण्डल रेल प्रबन्धक/इज्जतनगर सुश्री वीणा सिन्हा के मार्गदर्शन में मण्डल पर सभी स्टेशनों, टेज्नों एवं स्टेशन परिसरों तथा रेल पटरियों पर स्वच्छता कार्य किया गया। प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनों को सुचारू रूप से संचालित कराया गया तथा यात्रियों को बोतल क्रशर मशीन का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया गया, ताकि प्लास्टिक के बोतल बाहर न फेकें जांय। ज्ञातव्य है कि प्लास्टिक के बोतलों से नालियाँ और पानी की निकासी चोक कर जाती है। रेल यात्रियों तथा आम जनता को सफाई के प्रति जागरूक किया गया।

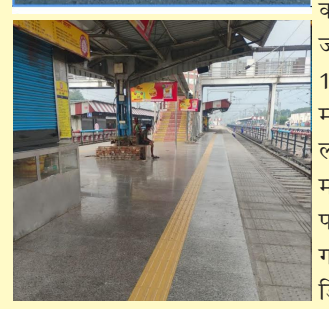

वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02 तथा एस.एल.आर.डी के 02 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे

गोरखपुर, : रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी दशहरा, दीवाली एवं छठ त्यौहारों पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुये 05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचलन नारंगी से 18 सितम्बर से 20 नवम्बर, 2025 तक (25 सितम्बर, 2025 को छोड़कर) प्रत्येक बृहस्पतिवार को तथा गोरखपुर से 19 सितम्बर से 21 नवम्बर, 2025 तक (26 सितम्बर, 2025 को छोड़कर) प्रत्येक शुक्रवार को 09 फेरों के लिये निम्नवत किया जायेगा। 05633 नारंगी-गोरखपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 18 सितम्बर से 20 नवम्बर, 2025 तक (25 सितम्बर, 2025 को छोड़कर) प्रत्येक बृहस्पतिवार को नारंगी से 13.20 बजे प्रस्थान कर गुवाहाटी से 14.00 बजे, कामाख्या से 14.20 बजे, रंगिया से 15.10 बजे, न्यू बंगाईगाँव से 17.13 बजे, कोकराझार से 17.52 बजे, न्यू कूचबिहार से 19.00 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी से 21.45 बजे, अलुआबाड़ी रोड से 22.29 बजे, किशनगंज से 22.55 बजे, बारसोई से 23.57 बजे, दूसरे दिन कटिहार से 01.30 बजे, नवगछिया से 02.20 बजे, मानसी से 03.08 बजे, खगड़िया से 03.20 बजे, बेगूसराय से 03.56 बजे, बरौनी से 04.45 बजे, शाहपुर पटोरी से 05.36 बजे, हाजीपुर 07.20 बजे, सोनपुर से 07.30 बजे, छपरा से 09.25 बजे, सीवान से 10.25 बजे तथा देवरिया सदर से 11.30 बजे छूटकर गोरखपुर 13.00 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, 05634 गोरखपुर-नारंगी साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 19 सितम्बर से 21 नवम्बर, 2025 तक (26 सितम्बर, 2025 को छोड़कर) प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 16.55 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 18.00 बजे, सीवान से 19.10 बजे, छपरा से 20.20 बजे, सोनपुर से 21.20 बजे, हाजीपुर से 21.35 बजे, शाहपुर पटोरी से 22.22 बजे, दूसरे दिन बरौनी से 00.15 बजे, बेगूसराय से 00.35 बजे, खगड़िया से 01.22 बजे, मानसी से 01.34 बजे, नवगछिया से 02.32 बजे, कटिहार से 06.30 बजे, बारसोई से 07.10 बजे, किशनगंज से 08.02 बजे, अलुआबाड़ी रोड से 08.40 बजे, न्यू जलपाईगुड़ी से 10.20 बजे, न्यू कूचबिहार से 12.30 बजे, कोकराझार से 14.02 बजे, न्यू बंगाईगाँव से 15.03 बजे, रंगिया से 18.30 बजे, कामाख्या से 20.10 बजे तथा गुवाहाटी से 20.40 बजे छूटकर नारंगी 21.40 बजे पहुँचेगी। इस गाडी में शयनयान श्रेणी के 16, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02 तथा एस.एल.आर.डी के 02 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे।

दूसरे दिन उत्तर रेलवे के लुधियाना स्टेशन से 12.05 बजे, जलंधर कैंट से 13.05 बजे छूटेगी

गोरखपुर, : रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 04652/04651 अमृतसर-जयनगर-अमृतसर विशेष गाड़ी का 02 मिनट का अस्थाई ठहराव उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के जलंधर कैंट एवं लुधियाना स्टेशनों तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के फेफना, बलिया, सहतवार एवं बकुलहा स्टेशनों पर निम्नवत प्रदान किया गया है।

-अमृतसर से 21 सितम्बर, 2025 से चलने वाली 04652 अमृतसर-जयनगर विशेष गाड़ी उत्तर रेलवे के जलंधर कैंट स्टेशन से 12.05 बजे एवं लुधियाना स्टेशन से 13.00 बजे तथा दूसरे दिन पूर्वोत्तर रेलवे के फेफना स्टेशन से 10.13 बजे, बलिया से 10.30 बजे, सहतवार से 10.55 बजे तथा बकुलहा से 11.17 बजे छूटेगी।

-जयनगर से 23 सितम्बर, 2025 से चलने वाली 04651 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के बकुलहा स्टेशन से 11.45 बजे, सहतवार से 12.07 बजे, बलिया से 12.27 बजे, फेफना से 12.45 बजे तथा दूसरे दिन उत्तर रेलवे के लुधियाना स्टेशन से 12.05 बजे, जलंधर कैंट से 13.05 बजे छूटेगी।

अमेरिकी टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार में घट रहे नए निवेशक, एनएसई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। टैरिफ झटकों के कारण अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की रिपोर्ट के अनुसार नए निवेशकों की संख्या मासिक आधार पर 18.3 प्रतिशत कम हो गई। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में एक्सचेंज में केवल 12.3 लाख नए निवेशक पंजीकृत हुए। यह चालू वित्त वर्ष में तीसरी बार सबसे कम मासिक वृद्धि है। मंदी के बावजूद, एनएसई का समग्र पंजीकृत निवेशक आधार अगस्त 2025 के अंत तक 11.9 करोड़ तक बढ़ गया। यह 12 करोड़ के महत्वपूर्ण मील के पत्थर के करीब है। नई पंजीकरणों में कमी मौजूदा आर्थिक मुश्किल हालात की वजह से आई है। टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं ने डाला असर इसमें कहा गया है कि टैरिफ संबंधी झटके और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विदेशी पूंजी के निरंतर बहिर्गमन ने हाल के महीनों में निवेशकों की धारणा पर प्रभाव डाला है।

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम बोर्ड ने किया स्वागत, मौलाना बोले कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं लेकिन

लखनऊ (संवाददाता)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को स्वीकार करने के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हुये कहा कि उन्हे उम्मीद है कि इस मामले पर पूरा फैसला आने पर मुसलमानो को पूर्ण राहत हासिल होगी। मौलाना ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा आज के जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने हमारी कुछ दलीलें स्वीकार कर उन प्रावधानो पर रोक लगायी है। हमे उम्मीद थी कि पूरे एक्ट पर स्टे दिया जायेगा मगर ऐसा नहीं हुआ है लेकिन कुछ अहम बातों पर स्टे दिया गया है जिसका हम स्वागत करते हैं। अभी पूरा फैसला आना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमे रिलीफ हासिल होगी। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की बेंच ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसके साथ ही, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का पांच वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य बताया गया था। फरंगी महली ने कहा फैसले में कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं हैं, लेकिन कई निर्णय हमारी उम्मीदों के अनुरूप है। हमें विश्वास है कि अंतिम निर्णय में भी हमारी दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया लेकिन कहा कि अंतिम निर्णय आने तक इसके कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संबंधित कानून के संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने 22 मई को उस कानून के विभिन्न प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए वक्फ के लिए संपत्ति समर्पित करने के लिए पांच साल तक इस्लाम का पालन करने के मानदंड के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित करने से पहले पांच वर्षों तक मुस्लिम होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धारा 3(आर), इस अनिवार्यता पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि राज्य (सरकार) द्वारा यह जांचने के लिए नियम नहीं बनाए जाते कि व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे किसी नियम,तंत्र के बिना, यह प्रावधान मनमाने ढंग से सत्ता का प्रयोग करेगा।

अखिल भारतीय गाली पार्टी बन गई है कांग्रेस, भूपेंद्र चौधरी ने कहा, जैसे इसके नेता, वैसे कार्यकर्ता

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अब अखिल भारतीय गाली पार्टी का स्वरूप ले चुकी है क्योंकि उसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कुछ भी ख्याल नहीं है। चौधरी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का या किसी बात का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन जनता द्वारा लगातार नकारे जाने से हताश और निराश कांग्रेस लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर असंयदित आचरण और अशिष्टता की सारी हद पार करने के काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के चित्र के साथ कांग्रेसियों ने आचरण किया है उससे साबित हो गया है कि कांग्रेस से मर्यादित आचरण की अपेक्षा करना बेकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में कांग्रेस अब अखिल भारतीय गाली पार्टी बन चुकी है। जैसे इसके नेता, वैसे कार्यकर्ता ! इनकी जितनी भी निंदा की जाए कम ही है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का रास्ता रोकने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कांग्रेस कार्यकताओं ने कड़ा विरोध किया है। रविवारर को लखनऊ में कांग्रेस की बैठक में पायदान पर दिनेश प्रताप सिंह का फोटो चिपकाया गई जिसको लेकर भाजपा ने तीखा विरोध जताया है।

खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने दिखाई सख्ती, ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा राशन! कार्ड होगा रद्द

लखनऊ (संवाददाता)। करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन रेखा की तरह काम करने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने राशन कार्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जी कार्ड को जांच के बाद निरस्त करने का फैसला लिया है। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिन्हें दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इनका सीधा असर करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। अब कार्डधारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि नमक, बाजरा और खाना पकाने का तेल जैसी वस्तुएं भी मिलेंगी। कई राज्यों में ये मुफ्त होंगी, जबकि कुछ जगह रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को गैस सिलेंडर पर भी छूट या मुफ्त सुविधा मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं और चावल मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो करने की योजना है। इससे बड़े परिवारों को राहत मिलेगी और पोषण स्तर में सुधार होगा। राशन कार्ड से जुड़े सभी लाभ पाने के लिए अब ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। इसमें आधार और जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने वालों का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

पैगाम-ए-अकरम और सीरत-ए-पाक, छोटे इमामबाड़े में रौशन हुई कॉन्फ्रेंस

लखनऊ (संवाददाता)। जिसे तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है, 18 रबीउल अव्वल 1447 की रात एक अजीम और रूहानी मंजर का गवाह बना। छोटा इमामबाड़ा, जो अपनी तारीखी और इल्मी हैसियत के लिए मशहूर है, रात 9 बजे एक बेमिसाल अंतर्राष्ट्रीय सेरत-ए-तैयबा कॉन्फ्रेंस के नूर से जगमगा उठा। यह खास मौका इसलिए भी यादगार था क्योंकि रसूल-ए-अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा (स.अ.व.) की पाक विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे थे। यह नूरानी महफिल आयतुल्लाहुल उजमा शेख मोहम्मद याकूबी दामत बरकातुहु के दफ्तर की जानिब से मुनककिद की गई थी, जिसका मकसद पैगम्बर-ए-इस्लाम की सीरत और उनके पैगाम को ताजा करना था। प्रोग्राम की सदारत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मौलाना सलीम अब्बास जैदी साहब ने फरमाई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के नामवर और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में आयतुल्लाह के नुमाइंदे और मुकर्रर हजरात ने अपनी मौजूदगी से रौनक बढ़ाई, जो भारत के मुखतलिफ सूबों में दीन-ए-मुबारक की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिर्जा आबिद अली साहब, जो बेंगलुरु से तशरीफ लाए, इस महफिल के खघस मेहमान थे। उनके साथ उनके मुआविन मौलाना रजा आगा साहब भी मौजूद थे।इसके अलावा, कश्मीर से मौलाना हकीम सज्जाद साहब, मुरादाबाद से मौलाना नबी हैदर साहब, दिल्ली के कघ्रीब से मौलाना फर्मान अली जैदी साहब, और बंगाल से मौलाना शेख मासूम अली साहब जैसे बुजुर्ग उलमा ने शिरकत करके महफिल की शनाखघ्त को और भी बुलंद किया। प्रोग्राम का आगाज कघरी एजाज हुसैन कश्मीरी साहब ने तिलावत-ए-कघुरआन के साथ किया, जिससे पूरी फजा पाक हो गई। उसके बाद कमाल वारसी कानपुरी साहब ने दिलकश अंदाज में नात पढ़ी, और वकार सुलतानपुरी साहब ने अपने अशआर से महफिल पर जादू कर दिया। प्रोग्राम की निजामत का फर्ज खघ्तीब-ए-शऊर गुलजार जाफरी ने बेहद खघ्बसूरती से निभाया। मौलाना सैयद हैदर अब्बास रजवी साहब ने सीरत और वसीयत के अहम पहलुओं पर खिताब किया, जिसके बाद डॉक्टर कलबे सब्तैन नूरी साहब ने मौजूदा दौर में सीरत-ए-पाक से इबरत हासिल करने के तरीकघें पर रौशनी डाली। मेहमान-ए-खघस मौलाना मिर्जा आबिद अली साहब ने आयाते अतरा और रिवायतों के हवाले से सीरत-ए-पाक और हुस्न-ए-अखलाक की अज्मत बयान की। इस कॉन्फ्रेंस की एक खघस बात यह थी कि सुन्नी भाइयों की भी नुमाइंदगी की गई। हजरत फजलुल मन्नान साहब, इमाम-ए-जुमा टिला वाली मस्जिद, लखनऊ ने नबी-ए-अकरम (स.अ.व.) के अल्काब और कुरआनी उपाधियों पर एक जाजिब बयान दिया, जिससे मिल्लत के बीच इत्तिहाद और मोहब्बत का पैगाम मजीद पुखघ्ता हुआ।

अभियंताओं के पद भरो और निजीकरण छोड़, उपभोक्ता सेवा करें

लखनऊ (संवाददाता)। वर्तमान में रिक्त पदों के सापेक्ष लगभग 350 सहायक अभियंता और लगभग 350 अवर अभियंता के पद है। अभियंता दिवस पर उपभोक्त परिषद ने सवाल उठाये कि खाली उन पर कब भर्ती होगी। वर्तमान में उपभोक्ताओं की संख्या के सापेक्ष राष्ट्रीय मानक के अनुसार सहायक अभियंता और अवर अभियंता के पद पर ही लगभग 2000 भर्ती की जरूरत है। आज 15 सितंबर अभियंता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन पर बोला करारा हमला कहा निजीकरण का फैसला समाप्त करके भारतीय अभियान चलाया जाए 3 करोड़ 61 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा के लिए उसके अनुपात में जो अभियंता होने चाहिए वह नहीं है। जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से आयोग द्वारा तय टैरिफ चार्ज की जा रही है तो उन्हें उपभोक्ता सेवा भी उच्च कोटि की मिलनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है उपभोक्ताओं के अनुपात में अभियंताओं की भर्ती वर्तमान में केवल रिक्त पदों के अनुसार यदि बिजली निगमो में भर्ती की बात की जाए तो लगभग सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं के 350 पद रिक्त होंगे। अवर अभियंताओं के भी लगभग 350 से 400 पद रिक्त होंगे वहीं अन्य जो पद टेक्नीशियन व अन्य पदों के हैं वह भी बड़ी संख्या में खाली है। दूसरी तरफ यदि उपभोक्ताओं के अनुपात में नए तरीके से पदों की गणना राष्ट्रीय मानक के अनुसार की जाए तो वर्तमान में सीधी भर्ती के तहत बिजली निगमो में लगभग 1000 सहायक अभियंता और 1000 अवर अभियंता के पद तत्काल भरे जाने चाहिए, तब सही मायने में विद्युत उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति व मानक के तहत उनके समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा। 1959 में गठित राज्य विद्युत परिषद के इतिहास में पहली बार पिछले दो वर्षों में सैकड़ो अभियंताओं ने बरस लिया और बड़े पैमाने पर निर्देश को को बर्खास्त किया गया इसकी भी जांच सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा निजीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली निगमो में अभियंताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका खामियाजा सीधे तौर पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। वर्तमान में बिजली निगमो में अभियंताओं की मानसिक स्थिति का एक्सपर्ट कमेटी द्वारा आकलन कर लिया जाए तो ज्यादातर फील्ड में तैनात अभियंताओं की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसका नतीजा यह है कि वह उसका गुबार विद्युत उपभोक्ताओं पर निकलते हैं। निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त अभियंता है उन्हें बर्खास्त होना चाहिए। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि उनका किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न होने पाए, जिससे वह पूरे मनोयोग से उपभोक्ता सेवा में अपना योगदान दे सके।

लखनऊ में गूंजेगी निकाय कर्मचारियों की आवाज

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ आने वाले 9 अक्टूबर को नगर निगम कर्मचारियों की ऐतिहासिक महारैली का गवाह बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आवाहन पर आयोजित इस महारैली को लेकर अवध क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। अवध क्षेत्र के अध्यक्ष रामकुमार रावत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष विजय यादव, महामंत्री जितेंद्र सिद्धार्थ, कार्यकारिणी सदस्य धीरज चौधरी, नंदलाल, दयाराम, जगदीश, लल्लन, धर्मेंद्र, पुत्तीलाल समेत बड़ी संख्या में फील्ड कर्मचारी रविवार को महुआ पार्क एवं विश्वास पार्क, इंदिरा नगर में जुटे। यहां पदाधिकारियों ने आगामी महारैली की रूपरेखा कर्मचारियों को बताई और आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। जन-जागरण अभियान में अध्यक्ष रामकुमार रावत, उपाध्यक्ष-विजय यादव, महामंत्री-जीतेन्द्र सिद्धार्थ, कार्यकारिणी सदस्य-धीरज चौधरी, जगदीश, फूलचंद, वारिस अली, पुत्तीलाल, नन्दलाल, लल्लन, धर्मेन्द्र, दयाराम, सहजराम, राजेन्द्र, शिवपाल यादव, आदि सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित हुएबैठक में यह तय किया गया कि 9 अक्टूबर की सुबह सभी कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पर 11 बजे इकट्ठा होकर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने एक स्वर में विश्वास दिलाया कि वे रैली में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यह महारैली निकाय कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों, नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों और सेवा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों को सरकार और प्रशासन के सामने मजबूती से रखने का माध्यम बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कर्मचारियों की आवाज को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष रामकुमार रावत ने कहा कि यह सिर्फ महारैली नहीं बल्कि निकाय कर्मचारियों की एकजुटता और हक की लड़ाई की शुरूआत है।

सूटकेस में था खुशबू वाला तेल, खोलते ही निकली 192 बोतल शराब, गोमतीनगर स्टेशन पर बड़ा खुलासा

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक ट्रेन के कोच से 192 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ये शराब एक लाल रंग के सूटकेस में सीट के नीचे छिपाकर रखी गई थी। दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शराब की तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे। यह घटना गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर घटी, जहां बरौनी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15204) आकर रुकी थी। जांच अभियान के तहत जीआरपी और आरपीएफ के जवान कोच संख्या डी-2 में पहुंचे। वहां एक सीट के नीचे लाल रंग का सूटकेस पड़ा मिला, जो संदिग्ध लग रहा था। जब जवानों ने सूटकेस के बारे में पूछा, तो शिवम जायसवाल और अवधेश वर्मा नाम के दो युवकों ने कहा कि सूटकेस उनका है। उन्होंने बताया कि इसमें श्खुशबू वाला तेलश रखा है। जब सुरक्षाकर्मियों ने सूटकेस खोलने को कहा तो दोनों युवक पहले टालमटोल करने लगे। बोले कि लॉक का पासवर्ड भूल गए हैं। संदेह बढ़ने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार सूटकेस खुलवाया। सूटकेस के अंदर से 192 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। यह शराब अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही थी, जहां इसकी बिक्री पर प्रतिबंध है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे लंबे समय से शराब की तस्करी कर रहे हैं। वे शराब को ट्रेन के जरिए बिहार ले जाते हैं और वहां ऊंचे दामों में बेचते हैं। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। इस बार भी वे शराब बिहार ले जा रहे थे, लेकिन चेकिंग में पकड़ लिए गए। जीआरपी और आरपीएफ की ओर से रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है।

विवाहिता की मौत,पति पर गला दबाकर हत्या का आरोप

लखनऊ (संवाददाता)। थाना बंथरा क्षेत्र के ग्राम भदोई में सोमवार को विवाहिता अंजू की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के पिता भोलाशंकर ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है। पिता के अनुसार, शादी के बाद से ही अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तीन साल पहले मारपीट के बाद दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में परिवार की इज्जत और बच्चों के भविष्य को देखते हुए समझौता कर लिया गया, लेकिन सुलह के बाद भी पति का व्यवहार नहीं बदला। सास के साथ भी घरेलू कामकाज को लेकर अंजू का विवाद होता रहता था। सूचना मिलते ही बंथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। रस्सी, कमरे की स्थिति और शरीर पर मौजूद निशानों की जांच की गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच से मौत के कारण का पता चलेगा।

ग्रामीण पर्यटन में सराहनीय कार्य के लिए कारिकोट गांव को आईसीआरटी अवार्ड

बहराइच का कारिकोट गांव बना रोल मॉडल: जयवीर

लखनऊ (संवाददाता)। बहराइच के कारिकोट गांव को होम-स्टे के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए नई दिल्ली में इंडियन सबकांटिनेंटल रिस्पांसिबल टूरिज्म आईसीआरटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीडीओ बहराइच मुकेश चन्द्र, ग्राम सचिव सुशील कुमार सिंह तथा कारिकोट की ग्राम प्रधान पार्वती को प्रदान किया। सतपाल महाराज ने पुरस्कार प्राप्त करने पर कारिकोट के प्रधान सहित ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण स्टे यूपी के सीमावर्ती जनपदों तथा उत्तराखण्ड के पर्वतीय इलाकों में काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष पूरे देश में इस नवाचार के रूप में अपना कर स्थानीय रोजगार तथा ग्रामीणों की आमदानी बढ़ाने के लिए इसकी शुरूआत की थी। यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए आज बताया कि कारिकोट गांव को मिला सम्मान पर्यटन विभाग के प्रयासों का परिणाम है। गांव ने ग्रामीण पर्यटन में विशेष पहचान बनाई है। सीमा पर्यटन जैसी अभिनव पहल भी की है। इन प्रयासों से स्थानीय समुदाय, खासकर युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है। गांव की संस्कृति, व्यंजन, हस्तशिल्प और लोक कलाओं को नई पहचान मिली है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म आईसीआरटी द्वारा कारिकोट गांव को शांति एवं आपसी समझ श्रेणी में प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। निर्णायक मंडल द्वारा इस उपलब्धि के लिए गांव को सिल्वर श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। आईसीआरटी द्वारा दिए जाने वाले ये पुरस्कार जिम्मेदार और सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कारिकोट गांव के लिए उपलब्धि ग्रामीण पर्यटन मॉडल को और मजबूत करने तथा शांति, सद्भाव और समावेशिता के मूल्यों को आगे बढ़ाने में प्रेरणा बनेगी।पर्यटन मंत्री ने बताया कि कारीकोट गांव भारत-नेपाल सीमा और हरे-भरे कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है। यह गांव जिम्मेदार पर्यटन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है। कारीकोट गांव के किसान ग्रामीण पर्यटन के अलावा बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती करते हैं। उन हल्दी को तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं पर है। हल्दी की खेती से महिलाएं जहां आत्मनिर्भर हुई हैं, इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी होता है। स्थानीय थारू समुदाय सहित समाज के अन्य लोगों की भागीदारी क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया ने बताया प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।उत्तर प्रदेश ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रूरल टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है।इसी कड़ी में कारिकोट गांव को मिला सम्मान विभागीय प्रयासों और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में की गई ठोस पहल का परिणाम है।कारीकोट सेंक्चुरी एरिया से घिरा क्षेत्र है, जहां विभागीय सहयोग से ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे ने गांव की तस्वीर बदल दी है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। कारिकोट के पास नेपाल की दो नदियों गेरुआ और कोरियाला का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सिंचाई विभाग के डैम को देखने का भी पर्यटकों में खास आकर्षण है। आगंतुकों को क्षेत्र हरीतिमा, जैव विविधिता, स्थानीय जीवनशैली, व्यंजन और हल्दी की खेती देखने का अनुभव मिलता है। प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर पर्यटक आते रहते हैं।

संक्षिप्त खबरें

मंदिर के दीये से घर में लगी आग,कमरे का सामान जलकर राख

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थानाक्षेत्र में सोमवार को मंदिर के दीये से घर में आग लग गई। महिला पूजा करने के बाद टहलने चली गई थी। दीये की आग घर में लग गई। जिसकी वजह से कमरे में रखा पूरा सामान जल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। इंदिरानगर बी-ब्लॉक निवासी मनोज वर्मा के मकान में दूसरी मंजिल पर गीता श्रीवास्तव दो बेटों के साथ किराए पर रहती हैं। सोमवार सुबह करीब 8 बजे गीता के कमरे से धुआं निकलने लगा। धुआं देखकर आसपास के लोग पहुंचे लेकिन घर बंद मिला। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर से लपटें निकलने लगीं। तभी किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गलियां संकरी होने से दमकल की गाड़ी घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। काफी दूर से पाइप फैलाकर आग को बुझाया गया। शुरूआती जांच में पूजा के दीपक से आग लगने की वजह सामने आई है। गीता पूजा का दीपक जलाकर टहलने चली गई थी।

राजधानी में बदला मौसम, कई इलाकों में रिमझिम बरसात

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में करीब एक सप्ताह बाद मौसम बदल गया है। सोमवार सुबह से गोमतीनगर, जानकीपुरम सहित कई इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है। धीमी हवा चल रही है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने की संभावना है। 2 दिन बाद बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रहा। दिनभर उमसभरी गर्मी पड़ती रही। इसके कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के मध्य भारत की ओर बढ़ने और मानसून द्रोणी के निष्प्रभावी होने के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी तराई, पूर्वांचल और मध्यांचल तक पहुंचेगी। इससे इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। खास तौर पर 17-18 सितंबर को राजधानी लखनऊ में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है।

भारत-ए की टीम ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ बैलेंस्ड होगी,चीफ कोच बोले- श्रेयस अय्यर तैयार

लखनऊ (संवाददाता)। भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच चार दिवसीय टेस्ट मैच से पहले इकाना स्टेडियम में दोनों टीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत-ए के चीफ कोच ऋषिकेश कनिटकर ने टीम इंडिया और कैप्टन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा टीम बैलेंस्ड है और श्रेयस अय्यर तैयार हैं। वह सभी फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं। उनका माइंडसेट क्लियर है। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने सेंचुरी जड़ी है। यह खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को मिलेगा। इसमें से अधिकतर प्लेयर्स दिलीप ट्रॉफी का मैच खेल चुके हैं। मुख्य कोच ने कहा कि इसमें यह नेक्स्ट लेवल है, जिसमें वह सीनियर टीम के लिए मौका पाएंगे। यह आइडल टूर्नामेंट है। इसमें अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी सीनियर टीम में खेलने का मौका पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया-ए के लिए खेलने वाले खिलाड़ी निश्चित तौर पर आगे सीनियर टीम का हिस्सा होंगे। हमारे स्पिन बॉलर्स निश्चित तौर पर हमारी ताकत हैं, लेकिन हमारा पेस अटैक भी अच्छा है। मजबूत है। टीम काफी बैलेंस्ड है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम बैलेंस टीम देखेंगे। ऑल राउंडर निश्चित तौर पर मजबूत हैं। बारिश के चलते मैच प्रभावित होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पिच के कंडीशन के हिसाब से हम काम करेंगे। यह सीरीज सीनियर टीम में खेलने से पहले का बड़ा मौका है। अभिमन्यु ईश्वरन अच्छा कर रहे हैं। वह चौलेंज के लिए तैयार हैं। उन्होंने बंगाल टीम को लीड किया है। काफी क्रिकेट ऊपर खेली है। उन्हें पता है कि क्रिकेट में कब क्या करना होता है। वह अच्छा करेंगे।

बीकेटी नगर पंचायत के 30 कर्मचारियों का वेतन अटका,दो महीने से नहीं मिली सैलरी

लखनऊ (संवाददाता)। बख्शी का तालाब स्थित नगर पंचायत कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे करीब 30 कर्मचारियों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेज अलीगंज के माध्यम से की गई है। कर्मचारियों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, फील्ड सुपरवाइजर, लाइट स्टाफ, नल स्टाफ, चौकीदार और चपरासी शामिल हैं। इन्हें जुलाई और अगस्त 2025 का वेतन नहीं मिला है। साथ ही जुलाई 2025 से पहले के कई महीनों का ईपीएफ भी जमा नहीं किया गया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को परिवार के इलाज, बच्चों की स्कूल फीस और अन्य खर्चों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी लखनऊ और बीकेटी नगर पंचायत कार्यालय के अधिशासी अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे काम करना बंद कर देंगे। बीकेटी नगर पंचायत कार्यालय के अधिशासी अधिकारी इंद्र भान के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन नहीं मिलने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

यूपी के तीन बीजेपी नेताओं को बड़ा दायित्व

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई हैं। कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के बीच पूर्वी क्षेत्र में समन्वय को लेकर बैठक हुई। बीजेपी और संघ के बीच बैठक में सरकार और बीजेपी के संगठन का संघ के पदाधिकारियों और कार्यकताओं के साथ तालमेल पर रणनीति बनी। सामंजस्य के लिए बीजेपी के तीन नेताओं को बड़ीजिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री के स्तर वाले मामलों के लिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री और संघ के बीच के तालमेल पर काम करेंगे। मंत्री स्तरीय मामलों को प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य देखेंगे। किसान मौर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह बीजेपी संगठन और संघ के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे।ये पदाधिकारी संघ से प्रकरणों को सरकार, मंत्री और पार्टी के संगठन तक पहुंचाएंगे और काम कराएंगे। सहमति बनी कि बीजेपी और संघ मिलकर समाज, छात्रों और शिक्षकों के बीच मिलकर काम किया जाएगा। क्षेत्रीय समन्वय बैठकें की जा रही है। छात्रों और विभिन्न समूहों में पैठ बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों के बीच पैठ बढ़ाई जाएगी। संघ की बैठक में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक कृपा शंकर, अनिल कुमार और प्रांत प्रचारक कौशल शामिल हुए और बीजेपी संगठन की ओर से यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने हिस्सा लिया।बैठक पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है।

सम्पादकीय

भारत-पाक मैच, भाजपा का नया प्रयोग

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की अनुमति देना मोदी सरकार का एक चालाकी भरा फैसला है। इसके जरिए भाजपा ने देश में एक नया प्रयोग करके देखा है कि जनभावनाओं को नियंत्रित करने की उसकी रणनीतियां, पैंतरें कामयाब हैं या नहीं। सूचना क्रांति के कारण हरेक क्षण में नयी खबर मोबाइल स्क्रीन पर उभरती है। हम एक खबर को ठीक से पढ़ कर उस पर मंथन कर सकें, इससे पहले नयी खबर उसे धकेल कर सामने आ जाती है। टीवी चौनल भी फटाफट वाले अंदाज में 1 मिनट में सौ खबरें सुनाकर दर्शकों को यह अहसास कराते हैं कि अब वो पूरी तरह से बाखबर है। आम नागरिक इस खुशफहमी में अब रहने लगा है कि देश-दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी सारी सूचना उसके पास है। हालांकि उसे इतना अवकाश नहीं दिया जा रहा है कि वह खबरों की पुष्टि करे या उसकी पड़ताल कर उसका विश्लेषण कर सके। सत्ता पर बैठे लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। भाजपा यह अच्छे से जानती है कि भारत और पाकिस्तान मैच में सबसे अधिक कमाई के मौके होते हैं। भाजपा यह भी अच्छे से जानती है कि जिस पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं, उसके साथ पहलगाम हमले के बाद मैच खेलने पर देश में सवाल उठेंगे। फिर भी भाजपा ने इस प्रयोग को करने का जोखिम उठाया, क्योंकि उसे पता है कि दोनों ही सूरतों में मुनाफा उसे ही होना है। अगर मोदी सरकार यह कहती कि हम पाकिस्तान के साथ किसी हाल में मैच नहीं खेलेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच उसकी साख बढ़ती। ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्धविराम हुआ और इस पर सरकार की किरकिरी हुई, तो यह एक अच्छा मौका नरेन्द्र मोदी के पास था कि वो अपनी छवि पर लगे दाग मिटा देते। लेकिन क्रिकेट मैच से होने वाली कमाई को देखते हुए मोदी सरकार ने मैच खेलने का फैसला लिया। यहीं उसने एक और प्रयोग किया। जिसके तहत भाजपा नेता अब जनता को यह समझा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच कभी नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप में सारी टीमें खेल रही हैं और हम मैच से पीछे हटेंगे तो हमारे प्वाइंट्स कम होंगे। इसलिए मजबूरी में मैच खेलना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान को हमने अब भी माफ नहीं किया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि बापू के अपमान पर प्रज्ञा ठाकुर को वो दिल से माफ नहीं करेंगे लेकिन संसद में प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की तारीफ की और मोदी अपना दिल ही टटोलते रह गए। बहरहाल, खबरों के तमाम प्लेटफार्म्स पर अलग-अलग तरीकों से इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है कि मोदी सरकार अब भी पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मैच खेलना मजबूरी है। भाजपा जानती है कि जनता का एक बड़ा वर्ग जो मुखर होकर मैच का विरोध कर रहा है, वह भी मौका लगते ही उसका मजा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को उलझाने के लिए न्यूज एंकर्स को भी भाजपा ने आगे कर दिया है, जो क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहूदे तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि इस मैच का बहिष्कार करो, हिम्मत है तो मैदान में मत उतरो। इन एंकर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अमित शाह से सीधा सवाल करें कि आप गृहमंत्री हैं और आपके अधीन आने वाली जांच एजेंसियों की विफलता के कारण पहलगाम हमला हुआ। आपके बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं और वो भारत-पाक मैच को रद्द नहीं करवा सके। अगर भारत को एशिया कप खेलना ही था तो टीमों का बंटवारा इस तरह भी हो सकता था कि भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे से खेलने की नौबत न आए, या उनके आपस में न खेलने से किसी को भी प्वाइंट्स का नुकसान न हो। लेकिन जय शाह ऐसा करते तो फिर मैच से होने वाली खरबों की कमाई भी हाथ से निकल जाती। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की जगह अब भाजपा चर्चा चला रही है कि खून और क्रिकेट साथ में चल सकते हैं, क्योंकि खेल, कला ये सब राजनीति से दूर रहने चाहिए। हालांकि इसी भाजपा सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों फवाद खान और हानिया आमिर की उन फिल्मों का प्रदर्शन रुकवा दिया है, जो भारत में बनी हैं। यू ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर कई पाकिस्तानी हस्तियों के एकाउंट्स बंद किए गए हैं। अपनी सुविधा से राष्ट्रवाद की परिभाषा और कायदे गढ़ने वाली भाजपा देश में प्रयोग कर रही है कि आखिर जनता को भटकाने में वह कहां तक कामयाब हो सकती है। भाजपा के लिए सत्ता और कमाई से बढ़कर कुछ नहीं है, यह बात एक बार फिर जाहिर हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के किसी भी मैच में विज्ञापनों, मैच की टिकटों, टीवी पर प्रसारण आदि से प्रत्यक्ष तौर पर सफेद कमाई होती है और सट्टेबाजी में परोक्ष तौर पर कमाई की जाती है। खरबों रूपयों की काली कमाई चंद मिनटों में स्विस बैंक जैसे खातों में पहुंचती है। सट्टेबाजी का यह धंधा राजनैतिक सरपरस्ती और प्रशासनिक सहयोग से चलता है। इसलिए क्रिकेट एसोसिएशन्स में राजनेताओं या उनके रिश्तेदारों को मुखिया बनाया जाता है। यह महज संयोग नहीं है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार में दूसरे स्थान पर सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमित शाह के बेटे जय शाह पहले बीसीसीआई में रहे और अब आईसीसी में चेयरमैन बने हैं।

नेपाल से सीखा सबक! भारत में आंदोलनों का अध्ययन कर भविष्य की रणनीति बनाएगी मोदी सरकार

मोदी सरकार की इस कवायद के वर्तमान संदर्भ में मायने समझें तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि आज भारत ऐसे समय में है जब सूचना और संचार तकनीक ने आंदोलन करने की शैली को बदल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन बहुत तेजी से आकार ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में यह निर्देश दिया है कि 1974 से अब तक देश में हुए प्रमुख आंदोलनों का गहन अध्ययन किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि किन कारणों से बड़े पैमाने पर असंतोष पनपता है और भविष्य में स्वार्थी तत्वों द्वारा आंदोलन की आड़ में अशांति फैलाने की संभावनाओं को रोका जा सके। देखा जाये तो 1974 का वर्ष भारतीय राजनीति में विशेष महत्व रखता है। यह वही दौर था जब जेपी आंदोलन ने बिहार से उठकर राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया और अंततः 1975 में आपातकाल की पृष्ठभूमि बनी। उसके बाद से छात्र आंदोलनों, किसान आंदोलनों, आरक्षण विरोधी और समर्थनकारी आंदोलनों, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन, शाहीन बाग का नागरिकता संशोधन कानून विरोध और हालिया किसान आंदोलन, ये सभी भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के निर्णायक पड़ाव रहे हैं। देखा जाये तो अमित शाह का यह कदम मात्र अतीत की घटनाओं की सूची तैयार करना नहीं है, बल्कि आंदोलन की प्रकृति, उनकी पृष्ठभूमि, उनसे हुई सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल और उनके सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों को समझना है। सवाल यह है कि कौन-से आंदोलन वास्तविक जनआकांक्षाओं के प्रतिनिधि थे? किन आंदोलनों को संगठित समूहों या बाहरी ताकतों ने दिशा दी? आंदोलन कब लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बने और कब हिंसा या अराजकता में बदल गए? इन सवालों का उत्तर ढूंढ़ना इस अध्ययन का मूल मकसद प्रतीत होता है। मोदी सरकार की इस कवायद के वर्तमान संदर्भ में मायने समझें तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि आज भारत ऐसे समय में है जब सूचना और संचार तकनीक ने आंदोलन करने की शैली को बदल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन बहुत तेजी से आकार ले सकते हैं। साथ ही स्थानीय असंतोष देखते-देखते राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इसके अलावा, विपक्षी दल और अंतरराष्ट्रीय मंच भी आंदोलनों को राजनीतिक रंग देने में सक्रिय रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय की इस पहल के कई मायने हैं। जैसे- सरकार आंदोलन के पीछे छिपी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझकर बेहतर नीतियाँ बना सकेगी। साथ ही अगर किसी आंदोलन को विदेशी या विध्वंसकारी ताकतें भड़काती हैं, तो उनकी पहचान करना आसान होगा। इसके अलावा, मोदी सरकार यह भी दशार्ना चाहती है कि वह लोकतांत्रिक अधिकारों और अनुशासन के बीच संतुलन कायम रखने के पक्ष में है। मोदी सरकार का यह निर्णय यह भी बताता है कि केंद्र सरकार आंदोलनों की राजनीति को सिर्फ तात्कालिक चुनौती नहीं मानती, बल्कि दीर्घकालिक नीति-चिंतन के विषय के रूप में देख रही है। हालाँकि, सरकार के इस फैसले की आलोचनाएँ होनी भी संभव हैं। विपक्ष इसे आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश कह सकता है। देखा जाये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन असहमति जताने का वैध साधन हैं, ऐसे में उनका अध्ययन करने को कुछ लोग नागरिक अधिकारों पर अंकुश की तैयारी मान सकते हैं। वैसे अमित शाह का यह निर्णय केवल अतीत को खंगालने का नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को दिशा देने का प्रयास है। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार आंदोलन की राजनीति को हल्के में नहीं ले रही और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता से जोड़कर देख रही है। अब देखना होगा कि यह अध्ययन संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है या फिर केवल आंदोलनों को स्वार्थी तत्वों की कारस्तानी करार देने तक सीमित रह जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नेपाल में जेन-जेड युवाओं के आंदोलन ने यह दिखाया है कि नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से असंतोष प्रकट करने के लिए सड़कों पर उतरने से हिचकती नहीं। इसके अलावा, दक्षिण एशिया के अन्य देशों– जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हाल में जन आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में अरब स्प्रिंग के उदाहरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता की असंतुष्टि, यदि समय रहते संभाली नहीं जाए, तो वह तख़्तापलट या शासन परिवर्तन का कारण बन सकती है। इसी पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी सरकार का 1974 से अब तक के आंदोलनों का अध्ययन करने का निर्णय महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह कदम केवल अतीत के आंदोलनों का विश्लेषण भर नहीं है, बल्कि भविष्य में असंतोष को किस रूप में प्रकट होने से रोका जाए, इसकी रणनीति तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम भी लगता है। बहरहाल, देखा जाये तो भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं, किंतु अगर इन आंदोलनों को बाहरी ताकतें या संगठित हित समूह मोड़ देते हैं तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए चुनौती बन सकते हैं। नेपाल या श्रीलंका जैसी स्थितियाँ भारत में नहीं उत्पन्न हों, यह सुनिश्चित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए अमित शाह का यह फैसला केवल आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और लोकतांत्रिक स्थिरता के संदर्भ में भी अहम है। इस तरह, मोदी सरकार का यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत अब आंदोलनों को सिर्फ लोकतांत्रिक असहमति का मंच नहीं मानता, बल्कि उन्हें संभावित भू-राजनीतिक खतरे और स्थिर शासन व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में भी देख रहा है। यही इसकी गंभीरता और प्रासंगिकता है।

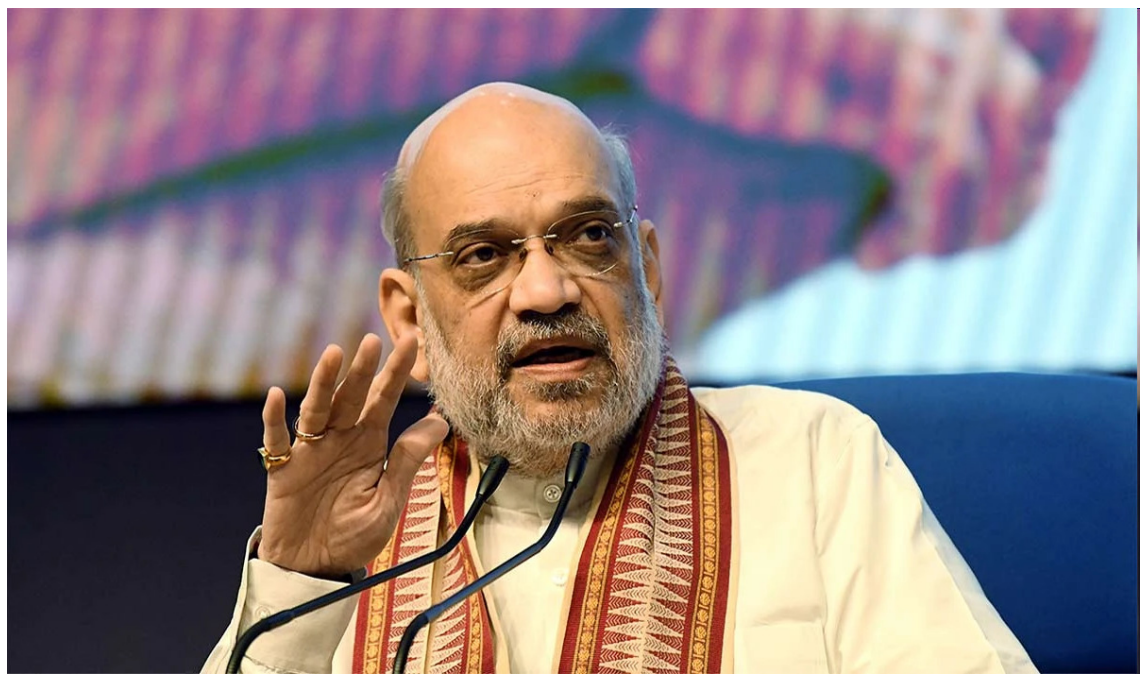

देश का राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण

संजीव ठाकुर

1947 में भारत एवं पाकिस्तान ने एक साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी किंतु पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा धारण कर अलग दिशा में आगे बढ़ता गया जिसके फल स्वरुप आज पाकिस्तान विपन्न और गरीब देश बन गया है। दूसरी तरफ भारत एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक अवधारणा की दिशा में नई-नई विकास के सोपनो को प्रतिपादित कर आगे बढ़ता गया। भारत वैश्विक स्तर पर सामरिक आर्थिक एवं अन्य विषयों पर काफी हद तक प्रगति प्राप्त कर चुका है।भारत ने आश्चर्यजनक रूप से देश को विकसित मजबूत एवं सशक्त बना दिया है। भारतीय परिदृश्य और संदर्भ में भारत में विगत एक दशक में व्यापक तथा आमूल चूल परिवर्तन देखे गये हैं। राजनीतिक परिदृश्य में उत्तरदायित्व आधारित शासन प्रशासन-प्रणाली, सांस्कृतिक विमर्श में सनातनी सांस्कृतिक सभ्यता-गौरव की पुनर्प्राप्ति और आर्थिक नीतियों के संरचनात्मक सुधारों ने देश की दिशा और दशा तय की है। इन नई विचारधारा एवं रणनीति ने भारत को न केवल आंतरिक रूप से सशक्त किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया। भारतीय राजनीति में पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा परिवर्तन रिपोर्ट कार्ड राजनीति का उदय रहा, जिसमें आम जनता और राजनीतिक नेताओं और दलों का मूल्यांकन उनके किए गए कार्यों और परिणामों के आधार पर कसौटी पर कसा जाने लगा है। संवैधानिक और नीतिगत स्तर पर कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन केंद्र की सख्त और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा विचारधारा का प्रतीक बना। तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीयता और शरणार्थी नीति पर नई विचारों की श्रृंखला को जन्म दिया। भारत की परंपरागत लोकतांत्रिक विरासत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए नया संसद भवन, ई-संसद और डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया तथा धनबल के प्रभाव ने लोकतांत्रिक विमर्श को चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भी बनाया गया है। नये भारत की संकल्पना और अवधारणा को केवल राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित परिसीमित नहीं रखा गया है बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यापक फलक पर भी इसका गहरा असर और परिणाम परिलक्षित हुए हैं । भारत की महान अवार्चीन योग और आयुर्वेद जैसी परंपरा को वैश्विक स्तर प्रचारित प्रसारित कर नई अवधारणा तथा पहचान प्रदान की गई है। अयोध्या में राममंदिर निर्माण ने भारतीय परंपरा और धार्मिक-सांस्कृतिक आकांक्षाओं की विशाल अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों में भारतीय आख्यानों और इतिहास को नवीन स्वरूप देने के प्रयास किए गए हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पुष्पित पल्लवित करने के प्रयासों को संपूर्ण प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही, सांस्कृतिक कूटनीति नवीन अवधारणा के माध्यम से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान और अधिक सुदृढ़ रूप से विस्तारित की है। हालाँकि, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ अनेक कठिन एवं दुष्कर चुनौतियाँ भी रहीं हैं। बहुलतावाद और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उठते सवाल तथा परंपरा बनाम आधुनिकता की खींचतान समाज में गूढ विचार विमर्श का विषय बनी रही। आर्थिक पुनर्जागरण के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने इस दशक में उल्लेखनीय और अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है । मेक इन इंडिया ने विनिर्माण और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। जीएसटी (2017) ने कर संरचना को एकीकृत और पारदर्शी बनाया। जीएसटी को 2025 में 22 सितंबर से नवीन संशोधन कर एकदम सरल एवं स्पष्ट कर काफी हद तक सस्ता करके आम जन को बड़ी राहत पहुंचाई है। डिजिटल इंडिया, जनधन योजना और यूपीआई ने वित्तीय समावेशन और नकदी रहित लेन-देन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाए। स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विदेशी निवेश वृद्धि, रेलवे और सड़क निर्माण में गति तथा बिजली और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार इस आर्थिक पुनर्जागरण के प्रमुख संकेतक रहे।इसके बावजूद बेरोजगारी की समस्या, ग्रामीणदृशहरी असमानता और आय-विभाजन जैसी बड़ी और गंभीर चुनौतियाँ भारत देश के आर्थिक परिदृश्य को संतुलित होने से रोकती रही हैं। कृषि सुधार अभी तक आधे अधूरे रह गए और हरियाणा पंजाब तथा अन्य प्रदेशों में किसान आंदोलनों ने यह यह साफ तथा स्पष्ट संकेत दिया कि विकास की अवधारणा सबके लिए समान रूप से सुलभ नहीं है।भारत ने पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान बनाई ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की भूमिका स्पष्ट हुई। 2023 में आयोजित ह20 सम्मेलनों में भारत ने वैश्विक मुद्दों पर संतुलित और निर्णायक नेतृत्व प्रस्तुत किया। चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में 10 महत्वपूर्ण देशों के साथ 27 देशों ने भारत चीन और रूस पर अपना विश्वास जाहिर कर यूरोपीय शक्तियों एवं मनमानी का खुला विरोध किया है।

मोदी राज में कमजोर होता लोकतंत्र

एस आर दारापुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, सितंबर 2025 तक, भारत में लोकतंत्र की स्थिति अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों, सूचकांकों और घरेलू हितधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है। हालाँकि भारत में नियमित चुनाव होते रहते हैं और प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाएँ कायम रहती हैं, फिर भी कई वैश्विक आकलन नागरिक स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे क्षेत्रों में मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 2014 में सत्ता में आने के बाद से पिछड़ने की ओर इशारा करते हैं। इन चिंताओं को अक्सर उन नीतियों और प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जिनके बारे में आलोचकों का तर्क है कि ये सत्ता को केंद्रीकृत करती हैं, असहमति को दबाती हैं और हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं। हालाँकि, समर्थक चुनावी स्थिरता, उच्च मतदाता मतदान, आर्थिक विकास और जन संतुष्टि सर्वेक्षणों को एक मजबूत लोकतंत्र के प्रमाण के रूप में देखते हैं। नीचे प्रमुख सूचकांकों, खूबियों, आलोचनाओं और व्यापक संदर्भ से प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है, जो सरकार समर्थक, आलोचनात्मक और तटस्थ दृष्टिकोणों सहित विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। कई स्वतंत्र संगठन मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों का उपयोग करके भारत के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं। यहाँ उनकी 2025 की रिपोर्टों (या 2024-2025 के रुझानों को दशार्ने वाले नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों) पर आधारित एक तुलना दी

गई है। फ्रीडम हाउस की विश्व में स्वतंत्रता पर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 63/100 (राजनीतिक अधिकाररू 31ध्40य नागरिक स्वतंत्रता 32/60) स्कोर के साथ आंशिक रूप से स्वतंत्र के रूप में चिह्नित किया गया हैय रैंक प्रदान नहीं की गई है।भारतीय लोकतंत्र को भाजपा के पक्ष में कथित चुनाव आयोग के पूर्वाग्रह, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल (जैसे, मार्च 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी), पेगासस जैसे स्पाइवेयर के माध्यम से अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध और मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा के कारण डाउनग्रेड किया गया है। वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत को चुनावी निरंकुशता (निरंकुशता के दौर से गुजर रहा) के रूप में वगीर्कृत किया गया है, उदार लोकतंत्र सूचकांक (एलडीआई)रू 0.29य रैंक 100/179 ।गिरावट 2008 में शुरू हुई लेकिन मोदी के कार्यकाल में तेज हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, पत्रकारों के उत्पीड़न और राजद्रोह तथा आतंकवाद विरोधी कानूनों का उपयोग करके नागरिक समाज पर हमलों में गिरावट आई। भाजपा द्वारा चुनावों में एकल-दलीय बहुमत खोने के बाद 2024 में कोई और गिरावट नहीं होगी, लेकिन यह ग्रो जोनष निरंकुशता में बनी रहेगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट (डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, 2025 में प्रकाशित) के अनुसार, भारतीय लोकतंत्र को 7.29ध10 के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वगीर्कृत किया गया हैय रैंकरू 41/167 स्कोर मजबूत चुनावी प्रक्रियाओं को दशार्ता है लेकिन नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संस्कृति में कमजोरियों को दशार्ता हैय एशिया का क्षेत्रीय स्कोर आंशिक रूप से भारत के रुझानों के कारण गिरा, जिसमें मीडिया की स्व-सेंसरशिप और विपक्ष को धमकी शामिल है। इंटरनेशनल आईडीईए (ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2024, 2025 अपडेट के साथ) के अनुसार, भारतीय लोकतंत्र को मध्यम श्रेणी का प्रदर्शनकर्ता माना गया है द्य प्रतिनिधित्वरू 73ध173य अधिकार 112/173य कानून का शासनरू 76/173य भागीदारी 99/173 निर्वाचित अधिकारियों और न्यायिक निगरानी में मजबूती (उदाहरण के लिए, 2024 में मनमाने ढंग से तोड़फोड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले)य अधिकारों में कमजोरियाँ, जिनमें 2025 में जातीय बंगाली मुसलमानों का निष्कासन और वक्फ संशोधन अधिनियम शामिल हैं, जिससे मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया है।ये सूचकांक आम तौर पर भारत की संकर स्थिति पर सहमत हैंकृन तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और न ही निरंकुशकृलेकिन 2014 के बाद से इसमें गिरावट देखी गई है, जिसमें वी-डेम ने इसे वैश्विक स्तर पर ष्सबसे बुरे निरंकुशष्देशों में से एक करार दिया है। भारत सरकार ने इस पर पलटवार किया है, आधिकारिक आख्यानों में लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करते हुए पश्चिमी उदारवादी मानदंडों पर सांस्कृतिक और चुनावी पहलुओं पर जोर दिया है, और रैंकिंग को पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज कर दिया है।

मणिपुर पर मरहम

लंबे समय तक अशांत रहे मणिपुर के मुद्दे पर अकसर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। अब वह प्रतीक्षित यात्रा हकीकत बनी है। कहा जा सकता है कि संघर्षरत राज्य की जनता के बीच विश्वास की कमी को दूर करने का यह सार्थक प्रयास जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाने का संकल्प जताया है। लेकिन मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति सरकार के संकल्प की परीक्षा लेगी। हालांकि,लगभग ढाई साल पहले भड़की जातीय हिंसा हाल के महीनों में, खासकर फरवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कम हो गई है। लेकिन भविष्य में हिंसा की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है। ऐसी दशा में इस संवेदनशील राज्य में केंद्र सरकार को सामान्य स्थिति की बहाली और दीर्घकालिक शांति स्थापना के लिये हर संभव प्रयास करने चाहिए। दरअसल,राज्य में स्थायी शांति के मार्ग में जो एक सबसे बड़ी बाधा है, वह है पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय और घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों के बीच लगातार कम होता विश्वास। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि दोनों समुदायों की आकांक्षाओं में संतुलन बनाए। ताकि दोनों समुदायों की चिंता और शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सके। विगत में मैतेई समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग करते रहे हैं। यह एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा था, जिसने कुकी-जो समुदाय के लोगों में असुरक्षा व अशांति पैदा कर दी। जिसे दूर किए जाने की सख्त जरूरत है। दरअसल, हाल के हिंसक संघर्ष ने राज्य में मतभेदों को मनभेद में बदल दिया है। कुकी-जो विधायकों के एक समूह, जिसमें भाजपा के भी सात विधायक शामिल हैं, ने कहा है कि दोनों पक्ष केवल अच्छे पड़ोसियों के रूप में शांति से रह सकते हैं,लेकिन फिर कभी एक छत के नीचे नहीं। उनकी मांग रही है कि गैर-मैतेई समुदायों के लिये अलग विधायिका सहित अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाए। यह सोच दोनों समुदायों के बीच गहरे मतभेद को उजागर करती है, जिसने मणिपुर को गहरी क्षति पहुंचायी है। इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनाव होने में अभी डेढ़ साल बाकी है। राज्य में हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है ताकि विधानसभा चुनाव में देरी न हो। केंद्र सरकार को विधानसभा को लंबे समय तक निलंबित रखने के फायदे और नुकसान का भी आकलन करना होगा। लेकिन फिलहाल, प्राथमिकता के आधार पर ध्यान विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर देने की जरूरत है। उससे भी महत्वपूर्ण, राज्य में सक्रिय चरमपंथी समूहों के लोगों को हथियार डालने के लिये प्रोत्साहित करने की जरूरत है। विकास परियोजनाओं पर काम जल्दी शुरू करने तथा उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने से भी मणिपुर के लोगों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसे तमाम प्रयास मणिपुर के आहत लोगों की विश्वास बहाली में मददगार साबित हो सकते हैं। निस्संदेह, इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

भारत के सिराज बने अगस्त के 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ', आयरलैंड की प्रेंडरगास्ट भी सम्मानित

दुबई (एजेंसी)। पुरस्कार मिलने पर सिराज ने खुशी जताते हुए कहा, 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए विशेष सम्मान है। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी एक यादगार सीरीज रही।' भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आइसीसी) ने अगस्त महीने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना है। सिराज को यह सम्मान इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। ओवल टेस्ट में दिलाई जीत सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ इस निर्णायक टेस्ट मैच में मैच में कुल नौ विकेट झटके। खासतौर पर अंतिम दिन उन्होंने तीन अहम विकेट लेकर इंग्लैंड को सिर्फ छह रन से हराने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को रिटेन किया। अवॉर्ड जीतने के बाद सिराज का बयान पुरस्कार मिलने पर सिराज ने खुशी जताते हुए कहा, 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए विशेष सम्मान है।

नो मेकअप, नो शो-ऑफ..राजेश खन्ना की नातिन की सादगी ने जीता सबका दिल

मासूमियत की हो रही जमकर तारीफ

बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ स्टार किड्स भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि, अभी तक कई ऐसे स्टार किड हैं, जिन्होंने एक्टिंग में डेब्यू नहीं किया, लेकिन अपने लुक्स से हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। इसी बीच एक और स्टारकिड लगातार चर्चा में बनी हुई हैं-नाओमिका सरन, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की नातिन हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कूब वायरल हो रहा है। दरअसल, हाल ही में नाओमिका अपनी मौसी ट्विंकल खन्ना के साथ स्पॉट हुईं। इस दौरान जहां ट्विंकल वेस्टर्न स्टाइल ब्राउन कोट-पैंट सूट में नजर आईं, वहीं नाओमिका ने पूरी तरह ट्रेडिशनल लुक अपनाया। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का सिंपल कॉटन सूट पहना और बाल खुले रखे। साथ में स्लीपर और खुले बाल। नाओमिका का ये लुक बेहद सिंपल था। बिना मेकअप, बिना किसी शो-ऑफ के, उनकी मासूमियत ने फैंस का दिल जीतती दिखी। कैमरे के सामने नजरें झुकाए वो शरमाते हुए कार में बैठती दिखीं। नाओमिका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और लोग उनकी तुलना बाकी स्टारकिड्स से कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि वो जाह्नवी कपूर, शनाया कपूर और अनन्या पांडे से भी ज्यादा खूबसूरत और सिंपल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाओमिका सरन जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी में हैं। वह अपना बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ कर सकती हैं। दोनों को कई बार प्रोडक्शन हाउस के बाहर साथ देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये जोड़ी एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में दिखाई देगी, जिसे दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया जाएगा। नाओमिका, ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन रिंकी खन्ना की बेटी हैं। रिंकी ने फिल्मों से दूरी बनाकर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और अब लंदन में रहती हैं। वहीं, अब उनकी बेटी नाओमिका फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए तैयार हैं।

परेश रावल ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग को लेकर किया बड़ा खुलासा, विवादों पर भी दी प्रतिक्रिया

हाल ही में परेश रावल ने बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग शड्यूल के बारे में खुलासा किया। साथ ही उन्होंने फिल्म को लेकर हुए विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। बॉलीवुड की पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हेरा फेरी' के तीसरे पार्ट की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी खुद परेश रावल ने दी है। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि किस महीने से शूटिंग शूरू होगी। इसके साथ ही अभिनेता ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर हुए विवादों पर भी बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग परेश रावल ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने हेरा फेरी 3 की शूटिंग पर कहा, ₹इस पर काम चल रहा है। हम अगले साल फरवरी-मार्च में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। विवाद पर क्या बोले अभिनेता आगे अभिनेता से सवाल पूछा गया कि क्या हेरा फेरी 3 को लेकर हुए विवाद ने निर्देशक प्रियदर्शन के साथ उनके रिश्ते को प्रभावित किया है? इसके जवाब में उन्होंने बताया, ₹बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इससे प्रियदर्शन के साथ मेरे रिश्ते में खटास नहीं आई है। ऐसा रिश्ता खराब नहीं होता है । वास्तव में, जो हुआ है वह यह है कि इसने हमारे समीकरण को और मजबूत कर दिया है। इन सबके माध्यम से, अब हम एक-दूसरे को और बेहतर तरीके से जानते हैं। घाव भर गया है । हमारा रिश्ता बहुत पारदर्शी है। मुझे नहीं लगता बाबूराव अकेले चल पाएगा परेश रावल ने आगे बातचीत में कहा, ₹ एक फिल्म सबकी वजह से बनती है । मुझे नहीं लगता कि बाबूराव अकेले चल पाएगा। आपको श्याम और राजू की भी जरूरत पड़ेगी। मैं लालची एक्टर नहीं हूं। मैं बेवकूफ भी नहीं हूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, जो यह मान ले कि दुनिया मेरी वजह से चलती है । अगर कभी कोई स्टैंडअलोन फिल्म भी बने, तो उसमें श्याम और राजू का होना जरूरी है। परेश रावल का वर्कफ्रंट परेश रावल की फिल्मों की बात करें, तो उन्हें आगामी फिल्म 'अजेयः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' में देखा जाएगा। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए करण जौहर ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख, दायर की याचिका

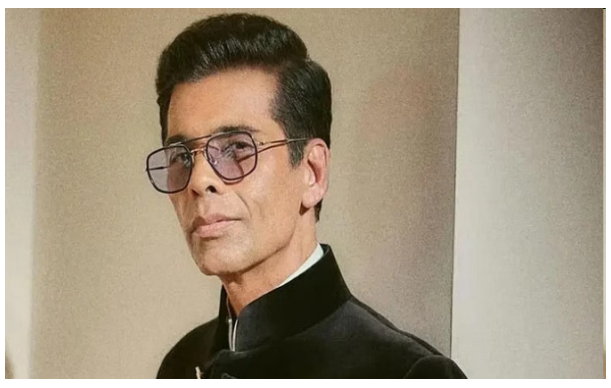

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बाद अब फिल्म निमार्ता-निर्देशक करण जौहर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानिए उन्होंने क्या मांग की है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के बढ़ते चलन के बीच सितारों की तस्वीरों और आवाज के साथ छेड़छाड़ कर उसके अवैध इस्तेमाल का खतरा भी काफी बढ़ा है। इसे लेकर फिल्मी सितारे सचेत हो रहे हैं। बीते दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अब फिल्म निमार्ता-निर्देशक करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निमार्ता ने की यह मांग न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, फिल्म निमार्ता करण जौहर ने व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने लोगों को उनके नाम पर अवैध रूप से सामान बेचने से रोकने की मांग की है। करण जौहर ने आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपनी पहचान और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। अपनी तस्वीरों और नाम वाले सामान की बिक्री पर रोक की मांग करण जौहर की यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिन्होंने उनके वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए शाम 4 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा करण जौहर ने अदालत से यह अनुरोध भी किया है कि कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित किया जाए कि वे उनके नाम और तस्वीर वाले मग और टी-शर्ट सहित अन्य सामान की अवैध बिक्री न करें। ओवेन कूपर ने सबसे कम उम्र में जीता एमी, ट्रैमेल टिलमैन बने अवॉर्ड जीतने वाले पहले अश्वेत कलाकार करण जौहर के वकील ने कही ये बात करण जौहर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा, 'मुझे यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि कोई भी अनधिकृत रूप से मेरे व्यक्तित्व, चेहरे या आवाज का इस्तेमाल न करे'।

जल्द मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ

अक्टूबर-नवंबर में घर गूंजेगी बच्चे की किलकारी

बॉलीवुड के फेमस कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर, 2021 में राजस्थान में धूमधाम से शादी रचाई थी। कपल की शादी को करीब चार साल हो गए हैं और कई बार इनके पेरेंट्स बनने की अफवाहें उड़ चुकी हैं। हालांकि, अब तक न तो विक्की और न ही कैटरीना ने प्रेग्नेंसी की ऑफीशियल अनाउंसमेंट की है। इसी बीच कपल के एक करीबी सूत्र ने कंफर्म किया कि कैटरीना अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और बच्चा अक्टूबर-नवंबर में आ सकता है। कैटरीना के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि वह एक एक्टिव मां बनना चाहती हैं। अक्टूबर-नवंबर में उनके घर बेबी आ सकता है। बच्चे के आने के बाद एक्ट्रेस लंबी मेटर्निटी लीव लेंगी। हालांकि, इन सब खबरों पर अभी तक विक्की-कैटरीना चुप्पी साधे हुए हैं। इससे पहले एक्टर विक्की कौशल से बैड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनकी पत्नी कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की चचाओं के बारे में पूछा गया था तो इस पर उन्होंने कहा था, ष्जहां तक खुशखबरी (प्रेग्नेंसी) की बात है, हमें इसे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी होगी, लेकिन अभी इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। अभी बस इंक दमू को एंजॉय कीजिए. जब अच्छी खबर आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। काम की बात करें तो विक्की कौशल आखिरी बार फिल्म छावा में देखा गया था, जबकि कैटरीना कैफ विजय सेतुपति के साथ फिल्म मेरी क्रिसमस में नजर आई थीं।

घर पर फायरिंग के बाद पहली बार सामने आई दिशा पाटनी की बहन, वीडियो में सेल्फ डिफेंस सिखाती दिखीं खुशबू

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी और उनकी बहन खुशबू पटानी के घर पर हाल ही में हमला हुआ था। उनके बरेली स्थित घर के बाहर कुछ अज्ञात बदमाशों ने ताबड़ तोड़ गोलियां चला दीं। गनीमत रही कि परिवार का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ। इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया था। वहीं, इस हमले के दो दिन बाद दिशा पटानी की बहन खुशबू ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे सेल्फ डिफेंस के टिप्स देती नजर आ रही हैं। वीडियो में खुशबू पटानी दिखाती हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी सिर्फ एक साधारण केबल की मदद से खुद को बचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सेना में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सिखाया गया था कि खतरनाक हालात में शांत रहकर और समझदारी से कैसे खुद को सुरक्षित किया जा सकता है। खुशबू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उनकी सोच और पहल की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने तंज भी कसा। एक शख्स ने लिखा मेडम, अगर एसी रूम के बाहर असली फाइट हो तो क्या ये काम करेगा? दूसरे ने कहा गोली चल गई ढांय वहीं, कई लोगों ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और पूछा कि क्या उनका परिवार अब सुरक्षित है। बता दें, घर पर हुए हमले के बाद दिशा पटानी न्यूयॉर्क फैशन वीक का हिस्सा बनीं और अपने लुक से सभी का ध्यान खींच लिया। दिशा इस इवेंट में डीप वी-नेक, स्ट्रैपी, सीक्विन मैक्सी ड्रेस में नजर आईं। उन्होंने खुले बाल, मिनिमल मेकअप और ब्लैक हाई हील्स के साथ अपने लुक को पूरा किया, जिसमें वे बेहद ग्लैमरस दिख रही थीं। बरेली फायरिंग को लेकर जगदीश पाटनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना को उनकी बेटी खुशबू के बयानों से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले के पीछे कोई गहरी साजिश है और परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

मौत के मुंह से बचकर निकली ये जानी-मानी एक्ट्रेस, बिग बी की इस ऑनस्क्रीन बहन के साथ हुआ था खौफनाक हादसा

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार वह एक भयानक आतंकवादी हमले का शिकार होने से बाल-बाल बची थीं? यह हादसा इतना खौफनाक था कि इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। हिंदी सिनेमा के दर्शक राधिका को खास तौर पर फिल्म आज का अर्जुन में अमिताभ बच्चन की बहन और नसीब अपना अपना में चंदो के किरदार के लिए याद करते हैं। हिंदी में भले ही उन्होंने कम फिल्में की हों लेकिन तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में उनका बहुत बड़ा नाम है और वह आज भी एक्टिंग में सक्रिय हैं। यह खौफनाक घटना साल 2019 में हुई थी। एक्ट्रेस राधिका श्रीलंका के जिस शांग्री-ला होटल में ठहरी हुई थीं उसी होटल को ईस्टर संडे के दिन हुए सीरियल बम धमाकों में निशाना बनाया गया था। कोलंबो और नेगोंबो के कई चर्चों और लग्जरी होटलों पर हुए इन हमलों में करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। राधिका की किस्मत अच्छी थी कि वह धमाके से कुछ घंटे पहले ही होटल से निकल चुकी थीं।

'नियमों से नवाचारों को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए', बोलीं वित्त मंत्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री ने 'विकसित भारत के लिए एआईः त्वरित आर्थिक विकास के अवसर' रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार न केवल एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके जिम्मेदार प्रयोग को भी सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए जानें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ऐसे नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के मामले में, दबाने के बजाय, जिम्मेदार तरीके से उसे बढ़ावा दें। वित्त मंत्री ने 'विकसित भारत के लिए एआईः त्वरित आर्थिक विकास के अवसर' रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार न केवल एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके जिम्मेदार प्रयोग को भी सुनिश्चित करना चाहती है। नीति आयोग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को जारी करने के बाद सीतारमण ने कहा,हम ऐसा नियमन नहीं चाहते जो सचमुच प्रौद्योगिकी को ही खत्म कर दे। हम नियमन चाहते हैं क्योंकि हम तकनीक का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं।

'हमारा लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है'

टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकी से भड़के ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा

ब्रासीलिया (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्राजील की सरकार पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार को एक बार फिर अमेरिका पर निशाना साधा और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ को अतार्किक और राजनीतिक बताया। अमेरिका ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। लूला ने न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रकाशित एक लेख में लिखा कि उनकी सरकार किसी भी ऐसी बात पर बातचीत के लिए तैयार है जिससे दोनों देशों को आपसी लाभ हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि 'ब्राजील का लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है'। अमेरिका ने ब्राजील पर लगाया है 50 प्रतिशत टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्राजील की सरकार पूर्व राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बोल्सोनारो पर अवैध रूप से सत्ता पर काबिज रहने का आरोप है। गुरुवार को ही ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने जेर बोल्सोनारो को साल 2022 में तख्तापलट के प्रयासों के लिए दोषी ठहराते हुए 27 साल की सजा सुनाई है। लूला की अमेरिका को दो टूक लूला ने लेख में लिखा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गर्व है क्योंकि यह फैसला ब्राजील की संस्थाओं और लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था की रक्षा करता है। लूला ने जेर बोल्सोनारो के खिलाफ बदले की भावना से काम करने के आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि यह फैसला महीनों की जांच के बाद आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मेरी, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हत्या की योजना बनाई गई थी। अमेरिकी टैरिफ पर निशाना साधते हुए लूला डी सिल्वा ने कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी न केवल गुमराह करने वाली है बल्कि अतार्किक भी है। उन्होंने कहा कि ब्राजील का लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है। अमेरिका की टिप्पणी पर ब्राजील ने जताई नाराजगी गुरुवार के फैसले के बाद अमेरिका ने तीखा बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जेर बोल्सोनारो को सजा होने पर पोस्ट किया कि ट्रंप सरकार परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाएगी। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने रुबियो की टिप्पणी को अनुचित धमकी बताया और कहा कि उनकी सरकार इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और बोल्सोनारो के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

सिख महिला से दुष्कर्म के मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने लोगों से की अपील

लंदन (एजेंसी)। वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र से ब्रिटिश सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'ओल्डबरी में एक युवा सिख महिला पर हुए भयानक हमले से मैं बेहद स्तब्ध हूं। यह हिंसक कृत्य है, लेकिन इसे नस्लीय भेदभाव के रूप में भी देखा जा रहा है, कथित तौर पर अपराधियों ने उससे कहा था कि वह 'यहां की नहीं है'।' ब्रिटेन में एक सिख महिला के साथ नस्लीय आधार पर हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय संदिग्ध व्यक्ति को संदेह के आधार पर रविवार को हिरासत में लिया गया। पिछले मंगलवार को इंग्लैंड के

वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के ओल्डबरी में 20 वर्षीय भारतवंशी महिला से दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने लोगों से की अपील वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि 'जांच अभी जारी है और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अटकलें न लगाएं क्योंकि हम उन सभी लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने का काम कर रहे हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं।' घटना को लेकर ब्रिटेन के सिख समुदाय में नाराजगी और गुस्सा है। वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र से ब्रिटिश सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'ओल्डबरी में एक युवा सिख महिला पर हुए भयानक हमले से मैं बेहद स्तब्ध हूं। यह हिंसक कृत्य है, लेकिन इसे नस्लीय भेदभाव के रूप में भी देखा जा रहा है, कथित तौर पर अपराधियों ने उससे कहा था कि वह 'यहां की नहीं है'।'

वंतारा जूलॉजिकल सेंटर को मिली क्लीन चिट

सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा- नियमों का हो रहा पूरा पालन

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि वंतारा में जानवरों की गैरकानूनी तरीके से खरीद की गई। याचिका में ये भी आरोप है कि हाथियों, चिड़ियाओं और अन्य संरक्षित प्रजातियों के जीवों को तस्करी कर वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के नाम पर वंतारा में लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी ने गुजरात के जामनगर स्थित वन्य जीव और पुनर्वास केंद्र 'वंतारा' को बड़ी राहत देते हुए उसे क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी के अधिकारियों ने वंतारा में नियमों के पालन और नियामक उपायों पर संतोष जताया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया और कहा कि अधिकारियों ने वंतारा में अनुपालन और नियामक उपायों के मुद्दे

पर संतुष्टि व्यक्त की है। वंतारा पर लगे थे ये आरोप यह रिपोर्ट शुक्रवार को पेश की गई थी और सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इसका अध्ययन किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत में दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं थी, जिनमें आरोप लगाए गए थे कि वंतारा में कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और साथ ही विदेशों से जानवरों, खासकर हाथियों के अधिग्रहण के आरोप लगे। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की। 25 अगस्त को एसआईटी का गठन किया था और जस्टिस जे चेलमेश्वर को इस एसआईटी का प्रमुख बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि वंतारा में जानवरों की गैरकानूनी तरीके से खरीद की गई। याचिका में ये भी आरोप है कि हाथियों, चिड़ियाओं और अन्य संरक्षित प्रजातियों के जीवों को तस्करी कर वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के नाम पर वंतारा में लाया गया। 1. भारत और विदेश से पशुओं, विशेषकर हाथियों का अधिग्रहण। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत चिड़ियाघरों के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन। 3. वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सीआईटीईएस) और जीवित पशुओं के आयात/निर्यात से संबंधित आयात/निर्यात कानूनों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन। 4. पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल, पशु कल्याण के मानकों, मृत्यु दर और उसके कारणों का पालन। 5. जलवायु परिस्थितियों से संबंधित शिकायतें और औद्योगिक क्षेत्र से निकटता संबंधी आरोप। वैनिटी या निजी संग्रह, प्रजनन, संरक्षण कार्यक्रमों और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से संबंधित शिकायतें।

'भारत-रूस के संबंधों को तोड़ने के प्रयास विफल होंगे', टैरिफ युद्ध के बीच मॉस्को का बयान

मॉस्को (एजेंसी)। मॉस्को ने कहा कि भारत-रूस की साझेदारी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। दोनों देशों के संबंध विश्वसनीय,

पूर्वानुमानित और रणनीतिक प्रकृति के हैं। रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाकर अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं अमेरिका द्वारा जी7 देशों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वे रूस से तेल खरीदने के लिए भारत के सामान पर भारी-भरकम टैरिफ लगाएं। इसे लेकर रूस ने बयान जारी किया है और कहा है कि भारत और रूस के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूस ने चेतावनी दी कि दोनों देशों को संबंधों को तोड़ने की हर कोशिश विफल होगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान रूस के विदेश मंत्रालय से मीडिया ने सवाल किया कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का भारत पर टैरिफ दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के टैरिफ दबाव के बावजूद भारत के अडिग रुख की तारीफ की। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का यह रुख भारत-रूस की दोस्ती की उस भावना और परंपरा में निहित है, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों में रणनीतिक स्वायतत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉस्को ने कहा कि भारत-रूस की साझेदारी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देती है। दोनों देशों के संबंध विश्वसनीय, पूर्वानुमानित और रणनीतिक प्रकृति के हैं। भारत और रूस नागरिक और सैन्य उत्पादन, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, परमाणु ऊर्जा और रूसी तेल अन्वेषण जैसी संयुक्त परियोजनाओं में मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी मंत्रालय ने नई भुगतान प्रणालियों के विकास, राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग बढ़ाने और वैकल्पिक परिवहन एवं रसद मार्गों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों पर भी जोर दिया।

स्थानीय चुनाव में मर्ज की पार्टी को मिले सबसे ज्यादा वोट, पर दक्षिणपंथी एएफडी की बढ़त सब पर भारी

बर्लिन (एजेंसी)। जर्मनी के नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया राज्य में हुए स्थानीय चुनाव में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी सीडीयू को सबसे अधिक 33.3% वोट मिले। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बढ़त धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी की रही, जिसने पिछले चुनावों की तुलना में अपने मतों को तीन गुना तक बढ़ा लिया। एएफडी ने प्रवासियों के खिलाफ असंतोष, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे बनाए थे। जर्मनी के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में हुए स्थानीय चुनावों में चांसल फ्रेडरिक मर्ज की पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले। हालांकि, असली जीत धुर दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) को मिली। इस पार्टी ने पांच वर्ष पहले की तुलना में अपने मतों में करीब तीन गुना बढ़त हासिल की है। सीडीयू, सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी (एसपीडी) कभी इस राज्य में मजबूत पकड़ रखते थे। एसपीडी को 22.1 फीसदी मत मिले। दोनों ही पार्टियों के मत प्रतिशत 2020 के स्थानीय चुनावों की तुलना में थोड़ा कम रहे। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा एएफडी का रहा। उसे 14.5 फीसदी वोट मिले, जो पिछले चुनावों की तुलना में 9.4 फीसदी की बढ़त है। यह पार्टी आमतौर पर पूर्वी जर्मनी में अधिक मजबूत मानी जाती है, जहां की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन इस चुनाव में उसने पश्चिमी जर्मनी में भी अपनी पकड़ बना ली है। फरवरी में हुए राष्ट्रीय चुनावों में एएफडी को 20.8 फीसदी मत मिले थे और वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस समय उसने नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया में 16.8 फीसदी मत हासिल किए थे।

अमेरिका में बड़े धमाके की साजिश नाकाम; यूटा में न्यूज चैनल की गाड़ी के नीचे मिला विस्फोटक, दो गिरफ्तार

यूटा (एजेंसी)। अमेरिका के यूटा में हाल ही राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की सरेआम हत्या के बाद एक और बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें कि मैग्ना इलाके में एक न्यूज चैनल की गाड़ी के नीचे विस्फोटक डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया है, हालांकि ये विस्फोट नहीं सका। मामले में एफबीआई ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के यूटा राज्य में एक बड़े धमाके की साजिश नाकाम कर दी गई। फॉक्स 13 न्यूज चैनल की गाड़ी के नीचे एक विस्फोटक डिवाइस मिलने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह डिवाइस असली थी और उसे जलाया भी गया था, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हो सका। इस मामले में 58 वर्षीय अदीब नसीर और 31 वर्षीय आदिल जस्टिस अहमद नसीर नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फॉक्स 13 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिवाइस शुक्रवार को गाड़ी के नीचे मिली थी। जांच में पता चला कि यह डिवाइस बेहद खतरनाक थी और अगर यह सक्रिय हो जाती तो आसपास के लोगों की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। इसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने मामला अपने हाथ में ले लिया क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला माना गया। शनिवार को एफबीआई ने सॉल्ट लेक सिटी पुलिस और यूनिफाइड फायर

बम स्क्वॉड के साथ मिलकर संदिग्धों के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान घर और आस-पड़ोस के कई घरों को खाली कराया गया ताकि किसी और विस्फोटक के खतरे को टाला जा सके। घर से मिले कई हथियार और ड्रग्स छापेमारी में एफबीआई को सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, बल्कि कई अन्य खतरनाक चीजें भी मिलीं। इसमें हथियार और गोलियां, विस्फोटक से जुड़ा सामान, अवैध नशीले पदार्थ और उनके उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल है, जिनमें सबूत मिलने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों पर पहले से ही प्रोटेक्टिव ऑर्डर लागू था, जिसके तहत उन्हें हथियार रखने की इजाजत नहीं थी। संदिग्धों के खिलाफ बड़े आरोप गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें आतंकवाद की धमकी, विनाशकारी हथियार रखने का आरोप, विस्फोटक उपकरण रखने का आरोप शामिल है। वहीं एफबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने जांचकर्ताओं से कहा था कि घर में पाए गए दो नकली विनाशकारी हथियार असल में असली थे। न्यूज चैनल ने बढ़ाई सुरक्षा, इलाके में दहशत फॉक्स 13 न्यूज की स्टेशन मैनेजर लीओना वुड ने कहा, 'हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अपनी रिस्क मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।' वहीं मैग्ना इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस और एफबीआई ने जांच तेज कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है या नहीं। इस पूरे मामले ने अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यूटा में ही ट्रंप समर्थक नेता की हत्या यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यूटा में ही एक और बड़ी घटना ने पूरे देश को हिला दिया। कंजर्वेटिव नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई।

कुशासन के खिलाफ 'गाउँ-गाउँ बाट उठ' से बुलंद हुई आवाज; अब अंतिम विदाई की पीड़ा

काठमांडो (एजेंसी)। नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बाद नई सुबह की शुरूआत तो हो चुकी है, लेकिन तथ्य यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। आंदोलन का एक और पहलू ये भी है कि इस देश में कुशासन के खिलाफ 'गाउँ-गाउँ बाट उठ' शीर्षक के प्रतीक गीत से युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। अब काठमांडो से पीड़ा के ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं जहां लोग अंतिम विदाई सह नहीं पा रहे हैं। नेपथ्य यानी रंगमंच के पीछे की वो जगह, जहां कलाकार मंच पर उतरने से पहले अपनी तैयारी करते हैं। नेपाल में जेन-जी के सड़कों पर उतरने में कुछ यही भूमिका लोकप्रिय म्यूजिक बैंड नेपथ्य ने निभाई। संगीत को समर्पित बैंड ने भले ही कभी ऐसे हिंसक आंदोलन की कल्पना न की हो, पर उसके गाने गाउँ गाउँ बाट उठ ने जेन-जी

में ऐसी ऊर्जा भरी कि वे भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने उतर पड़े। किस गीत ने युवाओं के आक्रोश को आवाज दी नेपाल में आठ सितंबर को विरोध-प्रदर्शन से एक दिन पहले म्यूजिक बैंड नेपथ्य ने अपने हिट गाने गाउँ-गाउँ बाट उठ, बस्ती-बस्ती बाट उठ की एक क्लिप साझा की, जिसका मतलब है-गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो। अगली सुबह नई ऊर्जा से भरे युवा मैतीघर मंडला में जुटे तो लाउडस्पीकर पर जगह-जगह यही गाना बन रहा था। यही गाना बजाया जा रहा था। इससे एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई, जिसे देखा और महसूस किया जा सकता था, क्योंकि युवा बदलाव की मांग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अपनों को खोने की पीड़ा पड़ोसी मुल्क के जेन-जी आंदोलन में अब तक 70 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। हिंसा, आगजनी और उपद्रव के दौरान अपनों को खोने वाले परिवारों में 28 साल के सुभालाल बालमई के परिजन भी हैं। सुभाष के अंतिम संस्कार के दौरान रविवार को परिवार के लोग रोने लगे।

नेपाल-फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में सरकार के खिलाफ आक्रोश

राष्ट्रपति ने लोगों से की शांति अपील

मनीला (एजेंसी)। पहले फ्रांस और फिर नेपाल में सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। इसमें जान-माल को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब फिलीपींस में भी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। इस सब के बीच राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सभी से शांति की अपील की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में फैले बड़े भ्रष्टाचार को लेकर जनता के गुस्से का समर्थन किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने विरोध को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होने चाहिए। राष्ट्रपति मार्कोस ने वादा किया कि इस घोटाले की जांच एक स्वतंत्र आयोग करेगा और इसमें उनके राजनीतिक सहयोगियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। टेलीविजन पर प्रसारित संसदीय सुनवाइयों में कई सांसदों, सरकारी इंजीनियरों और निर्माण कंपनियों पर भारी कमीशन खाने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा, 21 सितंबर को प्रदर्शन

राष्ट्रपति ने इस घोटाले का जिक्र पहली बार जुलाई में अपने वार्षिक संबोधन में किया था। हाल के दिनों में नेपाल और इंडोनेशिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों के विपरीत, फिलीपींस में अब तक विरोध प्रदर्शन छोटे और शांतिपूर्ण रहे हैं। अधिकतर गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जहां कैथोलिक चर्च के नेता, कारोबारी और रिटायर्ड जनरल खुलकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। 21 सितंबर को राजधानी मनीला में एक बड़े लोकतंत्र समर्थक स्मारक स्थल पर प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। 'मैं राष्ट्रपति न होता, तो सड़कों पर उनके साथ होता' राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा, 'अगर मैं राष्ट्रपति न होता, तो शायद सड़कों पर उनके साथ होता। मैं भी गुस्से में हूं। उन्हें बताओ कि उन्होंने तुमसे कैसे चोरी की, कैसे तुम्हें चोट पहुंचाई, जोर से चिल्लाओ, प्रदर्शन करो, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करो।' रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख बोले- सैनिक संविधान के प्रति वफादार हालांकि सरकार ने चेतावनी दी है कि कुछ लोग जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। रक्षा मंत्री गिलबर्टो टियोडोरो और सेना प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर ने साफ किया कि सेना 1,60,000 सैनिकों के साथ पूरी तरह गैर-राजनीतिक और संविधान के प्रति वफादार है। बाढ़ नियंत्रण परियोजना में क्या-क्या घोटाला?

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2016/67511 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा दीक्षित प्रिंटिंग प्रेस 120/51/1 मॉडल हाउस लखनऊ से मुद्रित एवं 233जी इंद्रलोक कॉलोनी कृष्ण नगर लखनऊ से प्रकाशित।
E-Mail : mantralko1008@gmail.com | सम्पादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 7007837917 | वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।